Policy WATCH

Volume XII, Issue 12
December 2023, New Delhi

Special Issue
(COVERING ALL THEMES)

In this issue

24 दिसंबर **2023** को सानेगुरुजी की **125** वी जयंती के उपलक्ष में
-डॉ. सुरेश खैरनार, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्र सेवा दल, नागपुर

White paper on the Telangana state's finances

रोजगार निर्माण के लिए एक रणनीति
- विजय महाजन, प्रशांत रेजी और जगमीत सिंह

Workshop Report: Conservation linked entrepreneurship and sustainable development of mountain districts of Uttarakhand
- Jeet Singh, RGICS

India's Foreign Policy since 2014: Continuity and Change
- Sneha Mahapatra, RGICS

Contents

Editorial....3

Constitutional Values and Democratic Institutions....4

1) 24 दिसंबर 2023 को सानेगुरुजी की 125 वी जयंती के उपलक्ष में- डॉ. सुरेश खैरनार, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्र सेवा दल, नागपुर....4

Governance and Development....11

2) White paper on the Telangana state's finances....11

Growth with Employment....13

3) रोजगार निर्माण के लिए एक रणनीति- विजय महाजन, प्रशांत रेजी और जगमीत सिंह....13

3.1 प्रस्तावना....13

3.2 2018 से 2024 के बीच अधिक रोजगार संभावनाओं वाले क्षेत्र....14

3.3 क्रियापद्धति और मॉडल....18

3.4 मॉडल के परिणाम....18

3.5 निष्कर्ष....21

3.6 संदर्भ सूचि....22

Environment, Natural Resources and Sustainability....23

4) Workshop Report: Conservation linked entrepreneurship and sustainable development of mountain districts of Uttarakhand- Jeet Singh, RGICS....23

4.1 Introduction....23

4.2 Entrepreneurship mindset....25

4.3 Significance of conservation linked entrepreneurship in Uttarakhand....27

4.4 Enterprise Ecosystem for Green Development in Uttarakhand....28

4.5 National Rural Livelihood Mission....28

4.6 Rural Enterprise Acceleration Project (REAP)....30

4.7 Conservation responsibilities and value added livelihoods....31

4.8 Carbon sequestration and trading of credits....34

4.9 Accessibility of technology and techniques to entrepreneurs....34

4.10 Major takeaways and recommendations....36

India's Place in the World....37

5) India's Foreign Policy since 2014: Continuity and Change- Sneha Mahapatra, RGICS....37

5.1 Introduction: why was 2014 a watershed?....37

5.2 Elements of change and continuity....44

5.3 Departure from earlier policy stances – Three examples....49

5.4 Shifts in style and substance....53

5.5 Conclusion....58

RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

Editorial

The Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies (RGICS) works on five themes:

1. Constitutional Values and Democratic Institutions
2. Growth with Employment
3. Governance and Development
4. Environment, Natural Resources and Sustainability
5. India's Place in the World

We bring out the monthly Policy Watch on each of these themes sequentially and every sixth issue is a Special Issue, where we carry articles from each theme. This is a special issue in which we carry one article on each theme.

The first article is in Hindi, by Shri Suresh Khairnar and it is a biograpihcal tribute to Sane Guruji – the great social reformer of Maharshartra whose 125th birth anniversary was on 23rd Dec 2023. We include it under the theme Constitutional Values and Democratic Institutions as people like Sane Guruji did a lot to truly establish the founding values of our Constitution.

The next article under the theme Governance and Development carries the summary of a White Paper on State Finances issued by the newly elected Telangana government. It shows how the state (and indeed all major states) is in a precarious fiscal situation and their deficit financing just cannot be sustained. We have to examine the fiscal costs of all kinds of promises that are made before elections by all Parties.

The third article is also in Hindi on the theme of Growth with Employment. Written by the undersigned, and two former colleagues of the RGICS, it shows the dire need to change our growth model so that jobs are also created. The paper emphaises the need to invest in regenerating the natural resources – land/soil, water, forests – so as to restore the productivity of agriculture and thereby generate more jobs in rural areas and also enhance farmers' and agricultural workers' incomes.

The fourth article is on the theme Environment, Natural Resources and Sustainability and it describes a workshop held in Uttarakhand in which Mr Jeet Singh, Fellow, RGICS participated. It deals with the issue of how to promote enteprises which while generating jobs and incomes for the local hill people, also ensure environmental conservation.

The firth article on the theme India's Place in the World, is a review of the changes in India's foreign policy since 2014. It has been written by RGCS Fellow, Sneha Mahapatra under the guidance of Dr Somanth Ghosh, Senior Visiting Fellow.

We hope the readers find the above articles enjoyable and informative. We would appreciate any feedback.

Vijay Mahajan
Director, Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

Images Courtesy:
Google Images (free to use images)
freepik

1) 24 दिसंबर 2023 को सानेगुरुजी की 125 वी जयंती के उपलक्ष में

डॉ. सुरेश खैरनार, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्र सेवा दल, नागपुर

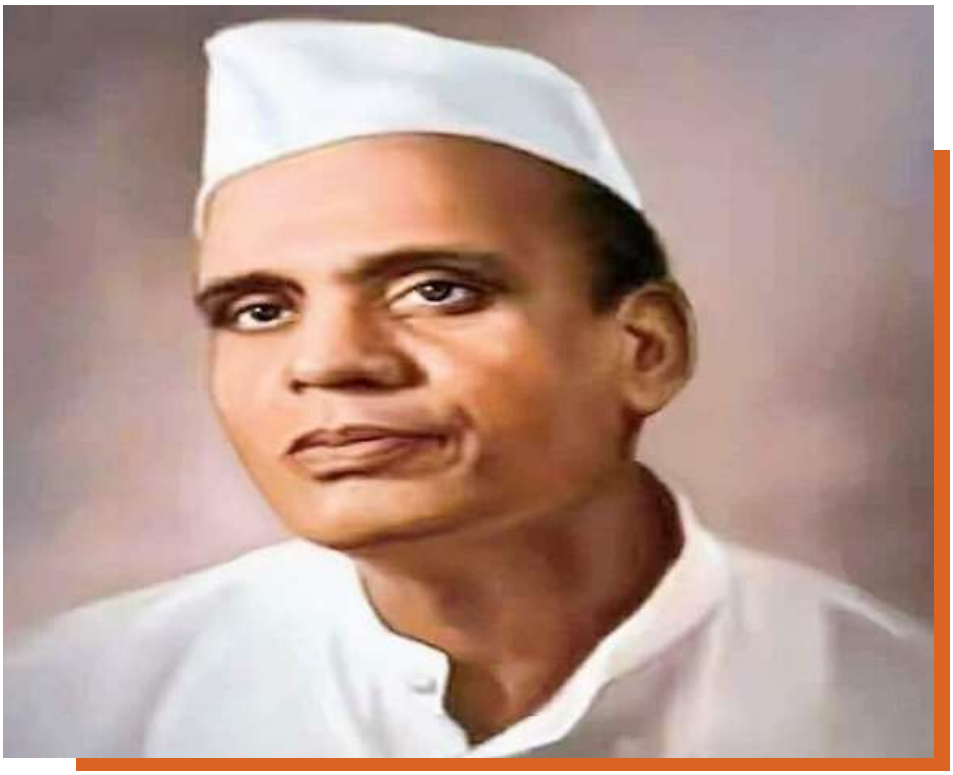

देश भर के राष्ट्र सेवा दल के तथा समाजवादी, आंतरभारती, सानेगुरुजी कथामाला और साप्ताहिक साधना परिवार के सभी साथीयो के नाम विनम्र निवेदन!

उन्नीसवीं शताब्दी के समाप्त होने के और बीसवीं शताब्दी शुरू होने के अंतिम सप्ताह में, 24 दिसंबर 1899 के दिन बीसवीं शताब्दी के शुरू होने के एक सप्ताह पहले महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के, पालगड नाम के तीन से चार हजार जनसंख्या वाले छोटे से देहात में सानेगुरुजी का जन्म हुआ था। यानी येशू ख्रिस्त के एक दिन पहले, और दो हजार एक सौ साल और इक्कीस दिन पहले, करूणा, प्रेम, दया और शांति के संदेश देने वाले भगवान येशू के जन्मदिन के सिर्फ एक दिन पहले समस्त महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के बाद (माऊली)के नाम से जाने जाने वाले मातृहृदयी सानेगुरूजी का जन्म हुआ।

शुरू के दिनों में भले ही आर्थिक स्थिति खाने-पीने के हिसाब से ठीक थी लेकिन भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में कब किसकी स्थिति बिगडेगी, यह कोई नहीं जानता एक तरह से जुआ ही होता है । उसी तरह से शिक्षा की व्यवस्था भी नहीं रहने के कारण, उन्हें प्राथमिक शिक्षा से हायस्कूल तथा उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत कष्टों से अपने एम.ए तक कि शिक्षा के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। इस कारण गरीबी, भुख तथा अभावग्रस्त परिस्थिती का सामना करते हुए, खुद के जीवन के अनुभवों से, गरीब तथा दबे-कुचले समाज के लिए स्वाभाविक रूप से नाता जुडा और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय उन्ही तबके के लिए काम करने मे गया।

हालांकि सानेगुरुजी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महाराष्ट्र के खान्देश के अंमलनेर नाम की जगह में प्रताप हायस्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए खान्देश एज्युकेशन सोसायटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में आए थे।

17 जून 1924 के दिन शिक्षक के रूप में जॉइन किया। लेकिन सिर्फ़ शिक्षक के काम के अलावा, संवेदनशील स्वभाव के कारण खान्देशके किसानों और मिल मजदूर वर्ग के लोगों की समस्याओं को लेकर आर्थिक - सामाजिक सुधार करने के लिए उन्होंने उनके संगठन खड़े किए और संघर्ष कीया।

मुख्यतः धुलिया-जलगांव, अंमलनेर के प्रताप मील के मजदूरों की युनियन और खान्देश के किसानों का संगठन खड़ा किया और उसके बलबूते पर, उस समय उनकी उम्र 25 साल की थी और देशभर में स्वतंत्रता की लड़ाई जारी थी।

छ साल शिक्षक की नौकरी करने के बाद 21 अप्रैल 1930 के दिन सानेगुरुजी ने चुपचाप अपनी नौकरी से खुद ही गायब होकर देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने का निर्णय लिया और अपने जीवन का पहला भाषण फैजपूर में दिया, जिस फैजपूर में छ साल बाद कांग्रेस का पहला ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय अधिवेशन 1936 के दिसंबर में संपन्न हुआ। एक तरह से सानेगुरुजी के जीवन का यह मोड आने वाले बीस साल तक अथक प्रयासों की दास्तान है।

17 मई 1930 के दिन सानेगुरुजी को, अंग्रेज सरकार ने अमळनेर की सभा में भाषण देते हुए राष्ट्र द्रोह के अपराध में पंद्रह महिनो की सजा सुनाई और धुलिया के जेल में बंद कर दिया। लेकिन धुलिया के जेल में नौजवानों को भड़काने के आधार पर, उन्हें ढाई महीनों के भीतर ही दक्षिण भारत के उस समय के मद्रास प्रांत के त्रिचनापल्ली जेल में लेकर गए और यही जेल में उन्होंने आंतरभारती की कल्पना की क्योंकि वह जेल एक मीनी भारत ही था। तीन हजार कैदियों में लगभग भारत के सभी प्रदेश के कैदियों की भाषा और संस्कृति का परिचय गुरुजी को हुआ था और वहाँ उन्होंने तमिल भाषा सीखने का प्रयास किया, और तमिल भाषा के संत कुरूवल्लूवर के प्रसिद्ध ग्रंथ 'कुरल' का अनुवाद किया।

कुरल को तमिल भाषा काऔर इसी जेल में विनोबा के गीता प्रवचनों को, सानेगुरूजी ने नोट्स लेने के कारण आज यह किताब की शक्ल में 'गीताई' के शिर्षक से उपलब्ध है | उस जेल में काफी भीड़ होने के कारण कुछ कैदियों को नासिक जेल में ले जाया गया जिसमें गुरुजी भी थे, और इसी जेल में उन्होंने उनकी सबसे चर्चित और प्रसिद्ध किताब 'श्यामू की माँ' का लेखन 36 रातो में पूरा किया। यह उनका एक तरह से आत्मचरित्र ही है और इसी किताब को पढकर महाराष्ट्र में एक पीढ़ी संस्कारित हुई है।

और आज भी काफी लोगों को प्रेरित करने का काम करती है। शायद मराठी की सब से ज्यादा मात्रा में बिकने वाली किताब में' श्यामची आई' का समावेश होता है, और इसी कारण आचार्य अत्रे ने 'श्यामची आई' पर मराठी में सिनेमा तैयार किया है, और शायद मराठी फिल्मों में पहली फिल्म है जिसे राष्ट्रीय स्तर का 'राष्ट्रपति सुवर्ण मयूर' पुरस्कार मिला है।

Source: Image

वेद माना जाता है। 'कुरल' का अर्थ दो चरण है, और 'कुरूवल्लूवर' में 1330 चरण है। इस तरह की महत्वपूर्ण साहित्य कृति का अनुवाद करने के अलावा पत्री नाम का काव्य संग्रह भी लिखा है। इस के अलावा गुरुजी ने चार नाटक त्रिचनापल्ली के जेल जीवन में लिखे हैं और कुछ अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा के साहित्यकारों के साहित्य का भी अनुवाद किया है। 23 मार्च 1931 के दिन सानेगुरुजी को त्रिचनापल्ली के जेल से रिहा कर दिया गया और उसी दिन लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव को रात में फांसी की सजा दी गई। तो गुरुजी ने अंमलनेर में उस सजा के खिलाफ सभा करते हुए अंग्रेज सरकार के इस कुकृत्य की भर्त्सना की है।

इसके बाद आचार्य विनोबा भावे के साथ खान्देशके दौरे में गुरुजीको जीवन में पहली बार साथ - साथ मिलकर घुमने का अवसर मिला था और उस कारण विनोबाजी के नजदीक जाने का भी और विनोबा के व्यक्तिमत्त्व को देखते हुए उन्होंने उनका चरित्र भी लिखा और 1932 में फिर धुलीया के जेल में साथ-साथ रहने का मौका मिला।

इसके पहले धुलीया जेल में ही उन्होंने रविंद्रनाथ टागौर के साधना और स्वदेशी समाज, इन दोनों किताबों का अनुवाद किया। विश्वप्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद करके, मराठी भाषी लोगों के लिए सानेगुरुजी ने बहुत बड़ा योगदान किया। अपने खुद के कविता, निबंध, कथा, उपन्यास के अलावा, अन्य साहित्य के अनुवाद कार्य में सानेगुरुजी के बराबर मराठी भाषी साहित्यकार दुसरा नही देखा। कुलमिलाकर 51 साल के जीवन में साहित्य, सार्वजनिक कार्य तथा उनके सहवास में आये युवा पीढ़ी को संस्कारित करने के उनके कार्यकाल को देखते हुए लगता है कि गुरुजी खुद ही एक स्कूल थे।

उसी के परिणाम स्वरुप 4 जून 1941 को राष्ट्र सेवा दल की स्थापना हुई। घोर सांप्रदायिकता के उपर खड़ा किया गया आर. एस. एस. के साथ मुकाबले हेतु ही राष्ट्र सेवा दल की स्थापना की गई है।

कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन को किसी देहात में आयोजित करने का श्रेय सानेगुरुजी को ही जाता है। खान्देश के जलगांव जिले के फैजपूर नाम के देहात में 1936, मतलब कांग्रेस की स्थापना के 51 साल बाद अधिवेशन फैजपूर में साने गुरुजी केअथक प्रयासों से संपन्न हुआ जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जिसमें 'राष्ट्र सेवा संघ,' नामक स्वयंसेवकों का अधिवेशन के लिए स्वयंसेवक संघठन का गठन करके अपने अगुआई में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रथम अधिवेशन संपन्न कराने के लिए सानेगुरुजी की मेहनत रंग लाई।

साने गुरुजि के जीवन का और महत्वपूर्ण पडाव हैं। जनवरी 1941 में धुलिया जेल में मधु लिमये बच्चों के वॉर्ड में बंद थे और उनकी और गुरुजि के साथ पहली आमने-सामने की भेंट। उस समय मधूजी गिनकर अठारह साल के थे और गुरुजी बयालीस पार कर चुके थे। मतलब एक पिता के उम्र के साने गुरुजी बेटे के उम्र के मधू लिमये के साथ धुलिया जेल में पहली मुलाकात में समझ जाते हैं कि यह लडका वैचारिक रूप से बहुत ही परिपूर्ण है और खान्देश के मिल मजदूर और किसानों के आंदोलनों के कारण गुरुजी कम्युनिस्टों की सोहबत में रहने के कारण कम्युनिस्ट प्रभाव में थे।

लेकिन दुसरे विश्वयुद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के ढुलमुल नितियो के बारे में पहले स्टालिन और हिटलर का समझौता हो चुका था। लेकिन हिटलर ने उसके बावजूद रशिया पर हमला करने के बाद कम्युनिस्टों का रवैया बदलकर वह लोकयुध्द बोलने लगे समाजवाद के उपर। मधू लिमये के धुलिया जेल में उन्नीस भाषण हुए और उन भाषणों की नोट्स साने गुरुजी ने लेने के कारण कम्युनिस्ट प्रभाव वाले गुरुजी एक बेटे के उम्र के लड़के के प्रभाव में आकर शुद्ध सोशलिस्ट बने।

और कम्युनिस्ट पार्टी के दुसरे महायुद्ध से लेकर बयालीस के भारत छोडो आंदोलन के दौरान भी विरोधी भुमिका के कारण सानेगुरुजी का कम्युनिस्ट पार्टी से पूरी तरह से मोहभंग हो गया और वैचारिक रूप से मधू लिमये के प्रभाव में आने वाले समय में रहे हैं। बहुत ही स्नेह और आदर गुरुजी मधूजी के बारे में रखते थे। यहां तक कहा जाता है "कि अगर गुरुजी और मधूजी के 1950 में अच्छी तरह से मुलाकातें होती तो शायद गुरुजी ने आत्महत्या नही की होती !"

और उसमें से आगे पांच सालों बाद, 4 जून 1941 को राष्ट्र सेवा दल की स्थापना करने की बात, एस. एम. जोशी, एन. जी. गोरे, भाऊसाहेब रानडे, शिरूभाऊ लिमये, अण्णासाहेब सहस्रबुद्धे इत्यादि समाजवादी लोगों के मन में आई, जिसे सानेगुरुजीअपना प्राणवायु कहा करते थे। और उसकी वजह आर. एस. एस. के स्थापना के सोलह साल पस्चात, बढती हुई घोर सांप्रदायिकता और जातीयता के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिए ही राष्ट्र सेवा दल का गठन किया गया है। यह बात मुझे बार - बार दोहराने की एकमात्र वजह - हम राष्ट्र सेवा दल के देशभर के फैले हुए लोग यह भुल गए हैं।

34 साल पहले अक्तुबर 1989, भागलपुर के दंगे के बाद मैंने यही बात राष्ट्र सेवा दल के अर्धशताब्दी के समय 1991 में विस्तार से तत्कालीन पदाधिकारियों को लिखे पत्र में लिखा था, "कि आने वाले समय में कम-से-कम पचास साल तक भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता ही रहेगा !" इसलिए राष्ट्र सेवा दल के पचास साल पुरे होने के उपलक्ष्य में आनेवाले पचास साल की भारत की संसदीय राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति के इर्द-गिर्द में रहने वाली है।

राष्ट्र सेवा दल के अर्धशताब्दी के समारोह में तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति के. आर. नारायणन प्रमुख अतिथी के रूप में आने वाले थे इसलिए मैंने अपने पत्र में आग्रह किया था कि "राष्ट्रपति के उपस्थिति में राष्ट्र सेवा दल आने वाले कम-से-कम दस साल सिर्फ सांप्रदायिकता के सवाल पर ही राष्ट्र सेवा दल के देशभर के कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई जानी चाहिए कि 1991 से 2001 तक का एक दशक, हमारे कार्यकर्ता प्रमुख रूप से सांप्रदायिकता के सवाल पर काम करेंगे।" यह पत्राचार गुजरात के दंगों के ग्यारह साल पहले का है और नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन की शुरूआत होने के पहले का है।

सानेगुरुजी अत्यंत संवेदनशील और कविहृदय के साहित्यकारों में से एक रहे हैं। उन्होंने सिर्फ मनोरंजन के लिए ही साहित्य नहीं लिखा है, अगल-बगल के शोषण तथा विषमता तथा अन्याय, अत्याचार तथा घोर सांप्रदायिक-जातियता के खिलाफ अपनी साहित्यिक रचना कथा, उपन्यास, कविता तथा उनके निबंध है। उदाहरण के लिए उनका लिखा हुआ मेरा सबसे प्रिय गित जिसे मैं यूनो का गित बनाने की इच्छा रखता हूँ, "सच्चा धर्म वहीं है जो दुनिया को प्रेम अर्पित करना चाहिए!" (खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे) जैसा अर्थपूर्ण गीत संत ज्ञानेश्वर के "पसायदान की बराबरी करता है"।

https://www.youtube.com/watch?v=bpQuFycSCvk

इसी तरह 'शामू की माँ 'नाम का उपन्यास, आत्मचरित्रात्मक लेखन, वैश्विक कलाकृती मे शुमार होता है जिसे पढकर महाराष्ट्र की कितनी पिढीयो को संस्कारित करने का श्रेय सानेगुरुजी को जाता है। कम-से-कम हमारे जैसे लोगों को संस्कारित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। जिस पर मराठी के मशहूर साहित्यकार और संपादक आचार्य अत्रे जी ने फिल्म भी बनाई है और प्रथम बार किसी मराठी फिल्मों में से राष्ट्रपति के स्वर्ण मयूर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उसी तरह भारतीय संस्कृति नाम की किताब, भारत की गंगा- जमुनी संस्कृति के महत्व को रेखांकित करते हुए भारत की बहुआयामी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय संस्कृति यह किताब भारत की सभी भाषाओं में अनुवाद करने की आवश्यकता है।

और इसी कड़ी में उन्होंने आंतरभारती की कल्पना अपने मृत्यु के पहले लिखी है, जिसमें भारत जैसे बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक देश के लोगों ने अपनी भाषा के अलावा अन्य प्रदेश की भी भाषा सीखने की कोशिश करनी चाहिए, और एक दूसरे की संस्कृति को जानने - समझने के लिए एक दूसरे प्रदेश में जाकर वहां के खान - पान, त्योहारों से लेकर साहित्य कला तथा भाषाएं भी सिखनी चाहिए, अन्यथा आजादी के बाद भी हमारे देश में आपस में ही मेलजोल नही होगा तो विश्व के विभिन्न देशों से क्या होगा?

सानेगुरुजी जैसे संवेदनशील लोग दुनिया में कभी-कभी ही पैदा होते हैं। हमारे देश में कविगुरू रविंद्रनाथ टागौर, महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, संत कबीर नानकदेव, बश्वेशरजी, महात्मा फुले, डॉ. राम मनोहर लोहिया, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, आचार्य जावडेकर, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण की कड़ी में सानेगुरुजी का नाम आता है।

कुल मिलाकर इक्क्यावन साल और पांच महीने और अठारह दिन के जीवन में महाराष्ट्र में एक पीढ़ी अपने खुद के सामने स्वतंत्रता, जनतंत्र, समता और सर्वधर्मसमभाव के मुल्यो के उपर समाज बनाने के लिये उन्होंने तैयार की है, और उसके बाद भी वह सिलसिला जारी है।

हम राष्ट्र सेवा दल के सैनिकों का भले ही सानेगुरुजी के मृत्यू (11 जून 1950) के बाद जन्म हुआ होगा, और हमें उन्हें देखने और सुनने का मौका नही मिलने के बावजूद उनके साहित्य और उनके सहवास में रहे मेरे पिताजी से लेकर, एस. एम. जोशी, एन. जी. गोरे, बैरिस्टर नाथ पै, मधु लिमये,प्रोफेसर मधू दंडवते, प्रोफेसर ग. प्र. प्रधान, यदुनाथ थत्ते, कवी वसंत बापट जैसे हमारे सार्वजनिक जीवन के पिता समान लोगों से जो भी सुना, पढा उससे हम राष्ट्र सेवा दल के सैनिकों का व्यक्तित्व बनने में बहुत मदद हुई है।

सानेगुरुजी का जन्म भले ही कोंकण में हुआ था और उनकी प्राथमिक शिक्षा कोंकण और महाविद्यालय की शिक्षा मुंबई तथा पुणे में हुई थी लेकिन उन्हें अपने शिक्षक की नौकरी के कारण महाराष्ट्र के खान्देश नामके आंमळनेर के प्रताप हायस्कूल मे शिक्षक की नौकरी और धुळे, जळगाव और नाशिक विभाग में अपना कार्यक्षेत्र, उनके सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कामो के लिए उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय खान्देश में रहा है, लगभग आधा जीवन।

प्रताप हायस्कूल का छात्रावास भी था। सानेगुरुजी को छात्रावास के अधिक्षक की अतिरिक्त जीम्मेदारी भी सौंपी गई थी जिस कारण सानेगुरुजी के भीतर का मातृहृदय प्रकट होकर, छात्रों को माँ के जैसा प्रेम और उनके बीमारी के समय जो सेवा सानेगुरुजी ने की, उसीके चलते उन्हें मातृहृदयी या माऊली (माँ) भी कहा जाता है। और इस तरह की सेवा का लाभ लिए विद्यार्थियों मे से कुछ महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन में आये मधुकरराव चौधरी, शिवाजीराव पाटील उनके बड़े भाई उत्तमराव पाटील, प्रकाश मोहाडीकर इत्यादी लोगों ने अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें मातृहृदयी कहा है।

सानेगुरुजी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी कार्य, पंढरपूर के विठ्ठल मंदिर मे हरिजन प्रवेश के लिए किया गया उपवास है। इसके पहले डॉ. बाबा साहब अंबेडकरजी ने नासिक के काला राम मंदिर के **1** मार्च 1930 के दिन छ साल तक मंदिर प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह किया था और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने उसी साल येवला तालुका जो नासिक जिले में ही आता है अपनी इतिहास प्रसिद्ध घोषणा की थी कि "मैं हिन्दू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं मरने के पहले हिंदू धर्म का त्याग अवश्य करूंगा।" लेकिन हिंदू धर्म के अंतर्गत कर्मठ लोगों के उंचनिंच भेद-भाव के कारण बीस साल पस्चात डॉ. बाबा साहब अंबेडकरजी को अपने लाखों अनुयायियों के साथ नागपुर में 1956 के 14 अक्तुबर दशहरे के दिन बौद्ध धर्म की दिक्षा लेनी पडी और हजारों सालों से यही सिलसिला जारी है।

क्योंकि अस्पृश्य समाज के लोग उस मंदिर की मूर्ति का दर्शन कर नही सकते और इसी कुप्रथाओं के कारण आज के ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम, क्रिस्चियन तथा हिंदू धर्म छोडकर गए हैं। और यह बात शिकागो जाने के पहले दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि, "भारत में क्रिस्चियन या इस्लाम धर्म का आगमन हमारे जाति-व्यवस्था के कंधों पर बैठकर ही हुआ है।" लेकिन इसके बावजूद तथाकथित हिंदूत्ववादी लोगों का गुस्सा अल्पसंख्यक समुदाय के उपर होने के मुख्य कारणों से यह भी एक कारण है।

इस बात पर सोच विचार करना तो दूर, उल्टा आज भी उत्तराखंड जिसका दूसरा नाम देवभूमि भी है, दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं है। और उसी उत्तराखंड के हरिद्वार के धर्म संसद 17, 18, 19 दिसंबर यानी आजसे एक सप्ताह पहले ही संपन्न हुई, जिसमें अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ जो जहरीले भाषणों की झड़ी लगाई गई है, उसके पीछे के कारण देखा जाए तो, हजारों साल पहले दलीतो ने जो हिंदू धर्म की घृणित जातीव्यवस्था के खिलाफ बगावत की है उसके खिलाफ गुस्सा जाहिर हो रहा है। लेकिन किसी भी वक्ता के मुहँ से हिंदू धर्म की उचनिच और उत्तराखंड के मंदिर दलितों के लिए खोलने की बात नहीं आई। उल्टा उन्हीं के पूर्वजों ने इसी जातीप्रथा से तंग आकर दुसरे धर्म को अपनाया क्योंकि उन्हें मस्जिद, गिरजाघरों में बराबर का प्रवेश मिला है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया की भाषा में "हिंदू धर्म की कट्टरपंथी और उदारपंथ की पांच हजार वर्ष पुरानी लड़ाई है, जो आज चरम सीमा पर हमारे देश में चल रही है!" हरिद्वार की धर्मसभा या कर्नाटक या देश के अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के उपर हो रहे हमलों के उदाहरणों से पता चलता है कि यह घृणा उसी बात को दर्शाते हैं। सवाल देश और प्रदेश की सरकारों की अकर्मण्यता का है। यह वही सरकारे है जिन्होंने दलितों तथा आदिवासी और महिलाओं के साथ हुई अत्याचारों की घटनाएं हुईं तो, उन्हें दबाने - मिटाने के लिए क्या-क्या नहीं किया? यहां तक की जांच तथा घटना के बारे में जानकारी लेने के लिए जाने वाले लोगों को देशद्रोह के कानून में जेलों में बंद कर दिया। और देश के भीतर गृहयुद्ध जैसे संगिन भाषणों को देखते हुए, कोई भी कोई कार्यवाही नहीं करना किस बात का प्रमाण है?

और प्रधानमंत्री, गृहमंत्री जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर बैठे हुए लोगों की चुप्पी, अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने की बात है। एक तरह से अघोषित हिंदू राष्ट्र की तरफ इशारा करते हुए, उन्होंने भारत की बहुआयामी संस्कृति को मिटाने की शुरुआत कर दी है। सानेगुरुजी के 125 वी जयंती के अवसर पर यह सब देखकर और भी हैरान करने वाली बात है।

1932 के ऐतिहासिक पुना पॅक्ट के बाद महात्मा गाँधी के नेतृत्व में हुई हरिजन यात्रा के दौरान, संपूर्ण देश में हजारों की संख्या में मंदिरों के कपाट हरिजनो के लिए खोले गए थे लेकिन कुछ मंदिरों में आज भी हरिजनो को प्रवेश नहीं है। यह बात साने गुरूजी जैसे संवेदनशील लोगों को बहुत अखरती थी। और महाराष्ट्र - कर्नाटक के सबसे लोकप्रिय मंदिर पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर में हरिजनो को प्रवेश नही था। देश की स्वतंत्रता नजर के सामने आ रही थी लेकिन हरिजनो के लिए विषमतावादी मानसिकता के कुछ लोगों के कारण प्रवेश वर्जित था,| इसलिये सानेगुरुजी ने 1946 के नवम्बर माह में समस्त महाराष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने वाली घोषणा कर दी कि जबतक पंढरपुर के मंदिर में हरिजनो को प्रवेश नहीं दिया जाता तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा।

इस खबर से संपूर्ण महाराष्ट्र में जबरदस्त हलचल मच गई। यह घोषणा बोर्डी नाम के मुंबई के नजदीक एक समुद्री किनारे स्थित गांव में जब गुरूजी अपने भाई के घर पर विश्राम करने के लिए गए थे उस समय किए, तो एस. एम. जोशी, मधु लिमये, सेनापती बापट, अच्युतराव पटवर्धन और शिरूभाऊ लिमये यह पांच लोग तुरंत बोर्डी गए और उन्होंने गुरुजी को समझाने की कोशिश की, कि इस तरह अचानक अनशन मत करो संपूर्ण महाराष्ट्र मे जनजागृती करने के बाद ही अनशन किजीये।

और इस तरह छ महिनों के प्रचार-प्रसार के बाद ही अनशन करने का निर्णय लिया गया। इन छ महीनों में राष्ट्र सेवा दल के कलापथक द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में, तथा अन्य लोगों की तरफ से मंदिर प्रवेश के आंदोलन का काफी जोर-शोर से प्रचार किया गया, लेकिन मंदिर के बडवे (पंडे) लोगों ने पासा फेंका की, अगर महाराष्ट्र का लोकमत मंदिर प्रवेश के तरफसे होगा तो मंदिर हरिजनो के लिए खोला जायेगा। लेकिन यह बडवे लोगों की एक राजनीतिक चालाकी थी। तो छ महिनों के बाद 1 मई 1948 के दिन साने गुरुजी और सेनापती बापटने पंढरपूर मे जाकर तनपुरे महाराज के मठ में आमरण अनशन शुरू किया।

और इस बीच काफी सारे घटनाक्रम हुए जिसमें महात्मा गाँधी के तारो से लेकर आचार्य विनोबा भावे के पत्राचार के बावजूद, गुरूजी का दस दिनों के उपवास के बाद, मंदिर के बडवे मंदिर के दरवाजे हरिजनो के लिए खोलने के लिये राजी हुए। 10 मई 1948 के रात साने गुरूजी ने 8:35 को अनशन की समाप्ति की। यह साने गुरुजी के जीवन की अंतिम समय की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता की सिर्फ़ कुछ औपचारिकताएं बाकी थी।

सवाल “आजादी के बाद भारत के जाति-धर्म निरपेक्ष समता मुलक जनतंत्र कैसे बनेगा?” और पंढरपुर के मंदिर प्रवेश की लड़ाई उन्होंने उसी के अनुसार लडी है। लेकिन सालभर के भीतर ही उन्हें निराशा ने घेर लिया कि भारत आजादी के बाद भी जो आदिवासी जंगल के बीच बाघों से नहीं डरता, लेकिन पुलिस या फॉरेस्ट के गार्ड से डरता है और अन्य समस्याओं को लेकर दुखी हो गये थे। सबसे ज्यादा महात्मा गाँधी की हत्या के कारण 11 जून 1950 के दिन उन्होंने इस दुनिया से विदा होने का निर्णय लिया।

शायद साने गुरूजी, जयप्रकाश नारायण जैसे संवेदनशील लोग जो देश-दुनिया के सवाल पर इतने संवेदनशील होते थे कि, लाखों की जनसंख्या वाले सार्वजनिक सभाओं में रोते थे। जोकि जेपी भले विवाहित थे, लेकिन जीवन भर प्रभावती जी के साथ रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया और सानेगुरुजी तो आजन्म अविवाहित रहे। इसलिये दोनों के पारिवारिक जीवन की समस्या नहीं थी, लेकिन दोनों लोगों की समस्याओं के साथ इतने घुलमिल गये थे कि वह समस्याओं को अपनी निजी समस्या समझ कर उससे दुखी हो जाते थे और भरी सभा में अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते थे। जिस तरह पिछले दो साल पहले के किसानों के नेता श्री. राकेश टिकैत के आंसुओं ने लगभग खत्म हो रहे किसानों के आंदोलन में जान फुकी है, यह आंसुओं के परिणाम का सब से ताजा उदाहरण है।

और साने गुरूजी जैसे अति संवेदनशील लोग इन समस्याओं से संबंधित भावनिक एकाग्रता होने के कारण स्वतंत्रता के तीन साल होने आए तो भी गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, और पुलिस के अन्याय - अत्याचारो को देखकर बहुत ही बेचैन होकर अपने आप को इस दुनिया से विदा होने का निर्णय ले लिया।

ऐसे लोगों की तुलना में हमारी-आपकी संवेदनाएं बहुत थोथी होती हैं, इस कारण हम लोग आराम से अपना जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। साने गुरूजी के जैसे लोग दुनिया में बहुत बिरले होते हैं। देश-दुनिया की स्थिति को देखते हुए, कुल मिलाकर अपने जीवन की अर्धशताब्दी पूरी करने के बाद उन्होंने दुनिया से 11 जून 1950 के दिन चले जाना पसंद किया। आज गुरुजी को हमारे बीच से शरीर चले जाने को 74 साल होने जा रहे हैं और जन्म के 125 साल। इस दरम्यान गत 30-35 सालों से सांप्रदायिक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अभी पूरे विश्व में क्राइस्ट के जन्मदिन के अवसर पर मेरी क्रिसमस मनाया जा रहा है लेकिन भारत में गत दो महीनों से लगातार चर्च तथा प्रार्थना स्थलों पर हिंदूत्ववादी लोग हमले कर रहे हैं।

आजादी के बाद के मुल्यो, तथा सानेगुरुजी जैसे संवेदनशील लोगो का सब से बड़ा पराजय है और सचमुच ही हम सानेगुरुजी के सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करने वाले सभी लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और मैं गत तीस सालों से भी ज्यादा समय से इस संकट के बारे में लगातार लिख-बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे साथियों को समझाने में मै अभितक कामयाब नहीं हो पाया हूँ। अब कोई भारत जोडो तो कोई नफरत छोडो जैसे सांकेतिक काम कर रहे हैं लेकिन सांप्रदायिकता तथा जाति-धर्म का द्वेष का प्रचार-प्रसार एक संघठन गत सौ साल से लगातार कर रहा है, और जिसके परिणामस्वरूप आज इतिहास के क्रम में इतनी सांप्रदायिकता नहीं थी जितनी आज फैल चुकी है।

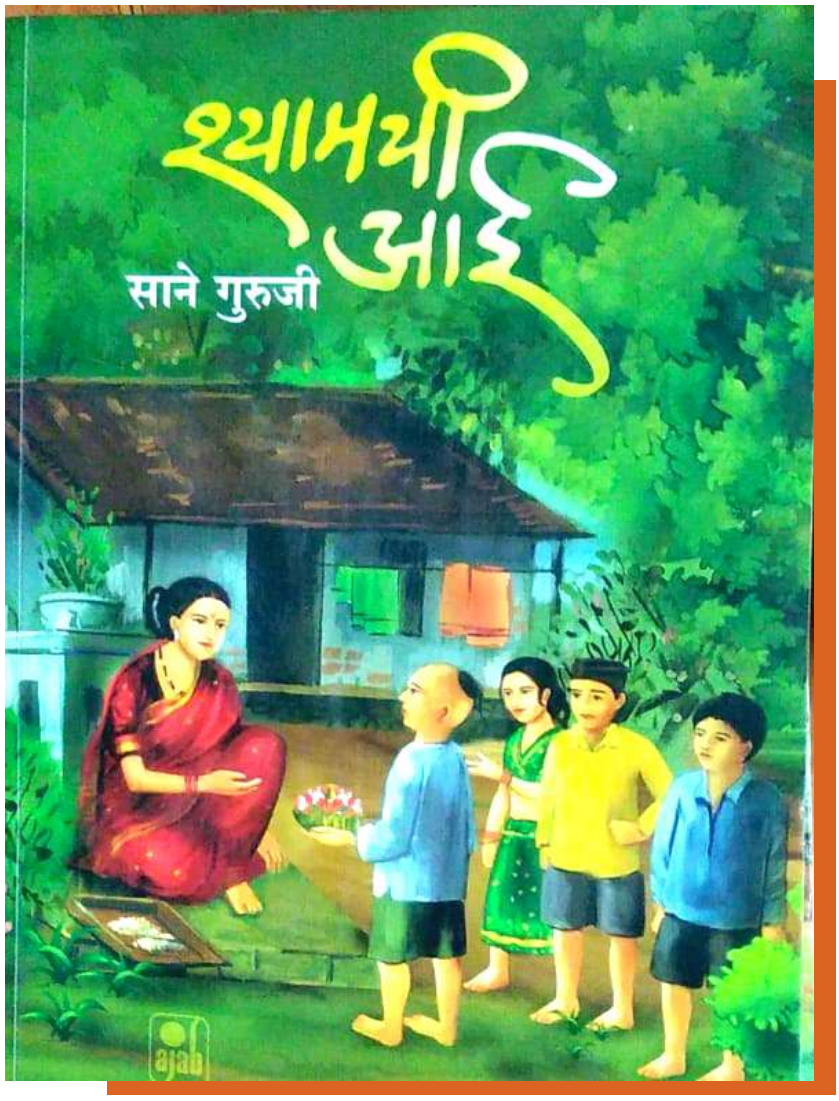

साने गुरूजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि उन्होंने जिन कारणों से अपने आपको इस दुनिया से विदा कर लिया था, उसे बेहतर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने अपने आपको झोंक देना चाहिए। अन्यथा हम यह लिखने-बोलने की स्थिति में भी रहेंगे की नही मुझे शंका है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्र सेवा दल के देशभर के साथियों की है जिसे सानेगुरुजी अपना प्राणवायु कहा करते थे।

2) White paper on the Telangana state's finances

In the last week of December 2023, less than a month after taking over, the new government of Telangana issued a white paper on the state's finances. We reproduced the summary below. At the end we also provide a table which shows the fiscal situation of all the major states. As can be seen the situation is alarming. The full paper can be downloaded from

https://cdn.telanganatoday.com/wp-content/uploads/2023/12/English-White-paper-revised.pdf

The principal tool in the hands of the state government to manage the finance is the state budget. In Telangana, there is a gap of almost 20% between the budgeted and the actual expenditure. This figure is not only high when compared to other states, but also in comparison to the expenditure achieved in the united Andhra Pradesh.

This gap in expenditure between the budget and actuals has meant that there is an accumulation of committed expenditure in terms of payments made for the services rendered by the suppliers and contractors and also to the employees. Further, there is a huge gap between the budgeted and actual money spent on major welfare schemes such as Dalita Bandhu and other welfare programs aimed at the welfare of ST, BC and minorities.

In united Andhra Pradesh, over a period of 57 years, an amount of ₹4.98 lakh crore was spent for development of Telangana region. With this money, substantial and tangible assets in terms of roads, irrigation projects, educational institutions, hospitals and power projects were created. In addition, the state facilitated - by giving lands and incentives to central public sector undertakings, defense establishments, thus paving the way for Hyderabad to be a pharma, defense and IT major in India.

In contrast, after the formation of the state, in the last 10 years, the total debt of the state and the SPVs has gone up to ₹ 6,71,757 crore from ₹ 72,658 crore in 2014-15. This gigantic increase in the debt (almost 10 times) has created an enormous fiscal stress on the state's finances in terms of its ability to service the debt. Further, no tangible fiscal assets in proportion to the money spent were created in the past 10 years.

The debt servicing burden of monies which are borrowed on the budget and off-budget has increased enormously and is consuming 34% of the state's revenue receipts. Further, the salaries and pensions of employees consume another 35% of the state revenue receipts.

This committed expenditure has meant that very little fiscal space is available for undertaking any welfare measures for the poorer sections of the society and growth enhancement measures for the development of the economy.

Consequently, the state has not been able to spend enough money on critical sectors such as Education and Health where the budgeted amount as the proportion of the total expenditure is amongst the lowest in the country.

A careful analysis of the above facts shows that Telangana state which was a revenue surplus state in 2014 and has one of the fastest growing economies in the country is now staring at a debt crisis. The rate of accumulation of the debt from off-budget borrowings has led to this situation. Every effort will be made to increase the state's resources and direct expenditures toward uplifting the impoverished, while reducing unnecessary spending. The new Government is determined to implement all the six guarantees which are promised by the party based on which the people of Telangana had given the mandate for change.

The Government is determined to overcome the fiscal challenges in a responsible, prudent and transparent manner. The white paper on state finances is the first step in this direction.

General Category States: Fiscal Deficit-to-GSDP Ratio

Sl. No.	State	Fiscal Deficit-to-GSDP ratio (2021-22)
1	2	3
1	Odisha	-3.1%
2	Jharkhand	0.7%
3	Gujarat	1.2%
4	Chhattisgarh	1.5%
5	Uttar Pradesh	2.0%
6	Maharashtra	2.1%
7	Andhra Pradesh	2.2%
8	Goa	3.2%
9	Karnataka	3.3%
10	Madhya Pradesh	3.3%
11	Haryana	3.6%
12	West Bengal	3.7%
13	Bihar	3.9%
14	Rajasthan	4.0%
15	Tamil Nadu	4.0%
16	Telangana	4.1%
17	Punjab	4.5%
18	Kerala	4.9%

Source: RBI State Finances – A Study of Budgets of 2023-24

Notes: 1. Gross Fiscal Deficit (GFD) receipts include revenue receipts and miscellaneous capital receipts.

2. GFD Expenditure includes revenue expenditure, capital outlay, and loans and advances net of recoveries.

3) रोजगार निर्माण के लिए एक रणनीति

विजय महाजन, प्रशांत रेजी और जगमीत सिंह

3.1 प्रस्तावना

इस सदी के पहले दशक 2001-2010 के मुकाबले, 2011 से शुरू हुए दूसरे दशक में भारत की जी. डी. पी. वृद्धि दर कुछ कम हुई । वृद्धि में गिरावट की वजह से साल 2017 के बाद से रोजगार बढ़ना थम गया। जून, 2019 में आधिकारिक तौर पर जारी किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी. एल. एफ़. एस जून 2017-जून 2018) (के आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए और इसे पूरी जनसंख्या पर लागू करते हुए, लेखकों ने अनुमान लगाया कि भारत में कोविड महामारी के दो साल पहले 2018 में कुल श्रम बल 45.8 करोड़ था।) 2018 में 43.2 करोड़ रोजगार प्राप्त कामगार थे (कार्यरत बल) तथा 2.7 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत अर्थात बेरोजगारी दर श्रम बल) का 5.8 फीसदी थी।

पी. एल. एफ़. एस. आँकड़ों (एन. एस. एस. ओ., 2019) के मुताबिक, 2018 में भारत में कामकाजी उम्र (15 साल से 64 साल) की एल. एफ़. पी. आर. 50.2 फीसदी थी। बल युवा वर्ग की एल. एफ़. पी. आर. 38.2 फीसदी थी। यह बताता है कि बहुत सारे युवा "शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण" (एन. ई. ई. टी.) में नहीं हैं। भारत में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी बहुत कम है | ग्रामीण इलाको की मात्र 18.2 फीसदी और शहरी इलाकों की मात्र 15.9 फीसदी महिलाएं ही श्रम बल में थीं। 2000 के दशक के मध्य से पहले से ही गिरी हुई महिला श्रम बल भागीदारी दर में तेजी से आई गिरावट, उसी 'U' संबंध को दिखाती है, जब उच्च आर्थिक वृद्धि के दौरान शायद महिला श्रम बल भागीदारी दर अपने न्यूनतम पर पहुंच गई (मेहरोत्रा और परीदा, 2017; मेहरोत्रा और सिन्हा, 2017; रेजी, 2019)।

Source: Image

कोविड महामारी के बाद निचला तबका पहले के मुकाबले कहीं अधिक आर्थिक तनाव महसूस कर रहा है| इसके चलते कहीं अधिक महिलाएं औरएन. ई. ई. टी (घर बैठे).युवा अपने-अपने परिवारों की आय बढ़ाने के लिए श्रम बल में आने के लिए मजबूर होंगे। ऐसे में शायद एल. एफ़. पी. आर. में गिरावट का फेर पलट गया |

निम्न लिखित तालिका से प्रतीत होता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2018 से 2023 तक 8.8 करोड़ नए व्यक्ति श्रम बल में जुड़े और 9.3 करोड़ व्यक्तियों को रोज़गार मिला क्योंकि इस बीच 0.5 करोड़ बेरोज़गारों को भी रोज़गार मिला|

2018-19 से 2021-22 तक रोजगार, एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूईआर और 2022-23 तक अनुमानित					
वर्ष	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (P)
का मापण	यूएस = पीएस + एसएस				
भारत की जनसंख्या करोड़ में	138.3	139.6	140.7	141.7	142.7
कामकाजी उम्र की आबादी करोड़ में	91.3	92.1	94.3	96.4	98.5
एलएफपीआर %	50.20%	53.50%	54.90%	55.20%	55.5%
श्रम बल करोड़ में	45.8	49.3	51.8	53.2	54.7
बेरोजगारी दर यूईआर %	5.80%	4.80%	4.20%	4.10%	4.0%
बेरोजगार श्रम बल करोड़ में	2.7	2.4	2.2	2.2	2.2
कार्यरत = श्रम बल में से बेरोजगार घटा कर करोड़ में	43.2	46.9	49.6	51.0	52.5
डब्ल्यूपीआर %	47.30%	50.90%	52.60%	52.90%	53.2%
संक्षिप्ताक्षर :					
यूएस = रोजगार की सामान्य स्थिति जिसमें मूल स्थिति (पीएस) और सहायक स्थिति (एसएस) शामिल है					
एलएफपीआर = श्रम बल भागीदारी दर डब्ल्यूपीआर = श्रमिक जनसंख्या अनुपात					
स्रोत : एलएफपीआर, डब्ल्यूपीआर और यूईआर के लिए विभिन्न वर्षों की पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट।					
https://dge.gov.in/dge/reference-publication-reports-annual					
https://www.macrotrends.net/countries/IND/india/population	वर्षवार जनसंख्या अनुमान के लिए				
https://www.statista.com/statistics/271315/age-distribution-in-india/	कामकाजी उम्र की आबादी के लिए %				

ज़मीनी स्थिति देखें से यह आंकड़ें मानने में मुश्किल लगती है | तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? हालाँकि रोज़गार में जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है परन्तु इनमे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हे केवल बिना पारिश्रमिक वाला घरेलू काम या बहुत काम आय वाला स्वरोजगार या कृषि कार्य मिला| ज़मीनी स्थिति देखें से यह आंकड़ें मानने में मुश्किल लगती है |

तो इसका स्पष्टीकरण क्या है? हालाँकि रोज़गार में जुड़े लोगों की संख्या बढ़ी है परन्तु इनमे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हे केवल घरेलू काम मिला है परन्तु कोई वेतन या पारिश्रमिक नहीं | इसके अलावा कृषि में काम करने वालों की संख्या बढ़ी है जबकि कृषि में पहले से ही आवश्यकता से अधिक लोग लगे हैं | कुछ बढ़ोतरी स्वरोज़गार में हुई है परन्तु आय के आंकड़ों से नहीं लगता के की यह बेरोज़गारी से बहुत बेहतर है| इस विषय पर विस्तार से टिपण्णी मेहरोत्रा (2023) में देखें |

3.2 2018 से 2024 के बीच अधिक रोजगार संभावनाओं वाले क्षेत्र

अगर हम श्रम बल में आने वाले सभी नए कामगारों और पुराने बेरोजगारों के लिए नीतिगत स्तर पर एक बड़ी सफलता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो 2018 से 2023 के बीच पूर्ण रोज़गार के लिए 11.1 . करोड़ रोजगार पैदा करने की जरूरत थी । । यद्यपि, हर कोई इस पर सहमत है कि रोजगार निर्माण की जरूरत है, चुनौती पर्याप्त गुणवत्तापरक रोजगार पैदा करने की है, जिनमें पर्याप्त भत्ता मिलता हो और मानवीय विकास एवं सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां हों।

सवाल यह है कि क्या इतने बड़े स्तर पर गुणवत्तापरक रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, खासकर पिछले दशक के निराशाजनक इतिहास को ध्यान में रखते हुए? केवल हां कहने से काम नहीं चलेगा।

हमें यह जवाब देना होगा कि आखिर अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों में ये रोजगार पैदा किए जा सकते हैं? और निवेश के किस स्तर पर? और सारी पूंजी कहां से आएगी? और यह जानते हुए कि पूंजी पर्याप्त नहीं होगी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवेश से अच्छे भत्तों वाले पर्याप्त रोजगार पैदा हों, उसके लिए नीतियों और संस्थानों को भी पुनर्गठित करना होगा।

किसी भी ऐसी अर्थव्यवस्था में जिसमें लगातार श्रम बल बढ़ रहा हो, उसमें लगभग सबके लिए रोजगार पैदा करना एक ऐसा उद्देश्य है जिसे पूरा करने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत होगी, ताकि रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी निवेश किया जा सके। इसके लिए गहन चिंतन की जरूरत है और इस पेपर में बमुश्किल से इसकी शुरुआत की गई है।

जहां तक बात रोजगार निर्माण की है, सभी सेक्टर एक जैसे नहीं हैं। निवेश के एक ज्ञात स्तर के साथ कुछ सेक्टर दूसरे सेक्टर्स के मुकाबले अधिक रोजगार पैदा करते हैं। रोजगार संभावना वाले क्षेत्र इस तरह से हैं: (महाजन (2021))

- जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उन्हें फिर से जीवित करना। जैसे- जल जंगल। जमीन,
- निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर निम्न आय आवासन और स्थानीय लघु स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर
- एक तरह के उद्योगों का घने झुण्ड वाले शहर (जैसे अलीगढ में ताले, मोरबी में घड़ियाँ) और छोटे कस्बों में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण
- श्रम केंद्रित सेवाएं

Source: https://sc0.blr1.cdn.digitaloceanspaces.com/article/111376-fesodklbrc-1615901787.jpg

हमारा मानना है कि कुल निवेश के लिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए- सार्वजनिक और निजी, दोनों। निजी निवेश अनुमानित फायदे को अधिकत सीमा तक पहुंचाने के तर्क पर चलेगा और इसे केवल उच्च रोजगार पैदा करने वाले सेक्टर्स को मिले प्रोत्साहनों के जरिए बल दिया जा सकेगा। हालांकि, सार्वजनिक निवेश को केवल उच्च रोजगार और साथ ही साथ सार्वजनिक उत्पादों और सकारात्मक बहिकारक पैदा करने वाले क्षेत्रों में ही प्राथमिकता दी जा सकती है।

इसे निजी निवेश द्वारा सहायता देने की जरूरत पड़ेगी, जिसे इन क्षेत्रों में उपयुक्त प्रोत्साहनों और निवेश पर फायदा लौटाने को सुनिश्चित करने वाले ढांचे के निर्माण के जरिए मोड़ा जा सकता है। यह पांच दशक पहले औद्योगिक क्षेत्र में और दो दशक पहले आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में निजी निवेश के आकर्षित करने के लिए किया गया था। इस प्रक्रिया को अब एक बार फिर से प्राकृतिक संसाधन क्षेत्र और साथ ही साथ सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए दोहराना होगा। इस दिशा में कुछ शुरुआत हो चुकी है और इस प्रक्रिया को लोकहित की रक्षा में तेज करना होगा।

जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है - उदहारण - जल, जंगल , जमीन, उन्हें फिर से जीवित करना।

हम पहले अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। कृषि सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है लेकिन लाखों कामगार और किसान अनिश्चित और कम आय के चलते इससे बाहर आ रहे हैं। इसकी जगह वो गैर-कृषि संबंधी कामकाज खोज रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी और बड़े शहरों में प्रवास के जरिए भी। लेकिन इसके बाद भी इस ट्रेंड को रोकना संभव है अगर कृषि के लिए जिन संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उन्हें फिर से जीवित करने के लिए निवेश किया जाए। ये संसाधन- हैं जल, जंगल, जमीन।

जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उनमें जलधाराएं, नदियां, जलाशय और भूजल एक्वीफायर्स; कटाई और चराई के चलते छंट चुके जंगल; रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग, सीमा से अधिक सिंचाई और मृदा अपरदन के चलते जिन खेतों की मिट्टी की हालत खराब हो चुकी है, इत्यादि शामिल हैं।

5.5 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक बंजर भूमि को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। वहीं दूसरी करीब 6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उच्च स्तर पर मृदा और जल संरक्षण की जरूरत है। इसके साथ ही झीलों, तालाबों, और टैंक्स की करीब 75 लाख हेक्टेयर भूमि को सुधार की जरूरत है। वहीं लगभग दो तिहाई जिलों में भूजल स्तर को फिर से उसकी पहली जैसी अवस्था में लाने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।

इधर, एक करोड़ हेक्टेयर की तथाकथित जंगली जमीन पर फिर से पर्याप्त वन रोपण करना है। ऐसे में जिन प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण हो चुका है, उन्हें फिर से जीवित करने के क्षेत्र में लाखों रोजगार संभावनाएं हैं। यद्यपि, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बहुत सारी योजनाएं जैसे एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चल रही हैं, इन्हें नई ऊर्जा दिए जाने की जरूरत है। प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग से लंबे समय तक रोजगार पैदा होने की संभावना बनेगी।

ध्यान देने की बात यह है कि इन रोजगारों का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण और जंगल वाले आदिवासी इलाकों में है, और शहरी इलाकों की परिधि में है, ठीक उन्हीं जगहों पर जहां रोजगारों की जरूरत है। इसके अलावा, इनमें से 90 फीसदी रोजगारों के लिए किसी भी तरह के कौशल और अर्धकौशल की ही जरूरत है। इससे अगले कुछ सालों में श्रम बल में मौजूद एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार पाने का रास्ता साफ होगा।

निम्न आय आवासन और स्थानीय लघु स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्माण क्षेत्र

निर्माण क्षेत्र में देखें तो आवासन और साथ ही साथ इन्फ्रास्ट्रक्चर में बड़ी संख्या में रोजगार निर्माण की संभावना है। उल्लेखनीय तौर पर दो करोड़ आवासों की कमी और मौजूदा आवासन के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत, साथ ही साथ बैंकों और वित्तीय कंपनियों की तरफ से हाउजिंग फाइनांस की उपलब्धता को देखते हुए यह कहना ठीक होगा कि इस क्षेत्र को वित्तीय बढ़ावे की नहीं, बल्कि एक नीति की जरूरत है। इसके अलावा, मौजूदा शीर्ष 100 शहरों के बाद अगले 1000 शहरों में आधारभूत ढांचे के निर्माण और सुधार की जरूरत सड़कों, पुलों और स्कूलों, स्वास्थ्य सेवा केंद्रों, पुलिस थानों और अस्पतालों जैसी सार्वजनिक इमारतों जैसे आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए कामगारों की उच्च मांग पैदा करेगी।

Source: https://prod-upp-image-read.ft.com/7bb7b670-1636-11e4-8210-00144feabdc0

रियल स्टेट और कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में लगी हुई श्रम शक्ति का लगभग 90 फीसदी हिस्सा भवन निर्माण में कार्यरत है, जबकि बाकी का 10 फीसदी हिस्सा भवन निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने, समापन, इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग, दूसरी इंस्टालेशन सेवाओं, विध्वंसन और काम की जगह को तैयार करने के कार्य में लगा हुआ है। रियल स्टेट और कन्स्ट्रक्शन क्षेत्र में 80 फीसदी से अधिक रोजगार बेहद की कम कौशल की जरूरत वाले होते हैं, जबकि 10 फीसदी कौशलपूर्ण कामगारों की जरूरत होती है। यह इस तथ्य के साथ मेल खाता है कि फिलहाल श्रम बल में निम्न स्तर के कौशल वाले कामगार मौजूद हैं और अगले कुछ सालों में उनका कौशल निर्माण हो जाएगा।

छोटे कस्बों में स्थित सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) में विनिर्माण

गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार, इस अनुपात में भी नहीं बढ़ा है कि मांग के कहीं आसपास भी ठहरे। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि कम बनी हुई है और इसके और कम होने की आशंका है क्योंकि व्यापक स्तर पर स्वचालन प्रयोग में आने लगा है। फिर भी, विनिर्माण क्षेत्र में, कृषि प्रसंस्करण के इर्द गिर्द नए रोजगार पैदा होंगे। ये रोजगार कृषि के स्तर पर उत्पादक इलाकों (जैसे पंजाब का दोआबा, मध्य प्रदेश का मालवा और आंध्र प्रदेश की तटीय पट्टी; और ग्रामीण इलाकों में सूक्ष्म उद्यमों जैसे हथकरघा और हस्तशिल्प) में पैदा होंगे। MSME क्लस्टर्स की बुनियाद के लिए चल रहे प्रोजेक्ट क्लस्टर ऑब्जरवेटरी के मुताबिक, ऑटोमोबाइल्स से लेकर पर्यटन तक भारत में अलग-अलग उत्पादों/सेवा श्रेणियों में 5600 से अधिक क्लस्टर्स काम कर रहे हैं।

क्लस्टर की श्रेणी	संख्या
औद्योगिक क्लस्टर्स	1416
हस्तशिल्प क्लस्टर्स	3403
हथकरघा क्लस्टर्स	608
सूक्ष्म् क्लस्टर्स	154

अगर SMEs को और अधिक उत्पादक और निर्यात-केंद्रित बनाया जाता है तो इन क्लस्टर कस्बों (जैसे पीतल के काम के लिए मुरादाबाद और होजरी के लिए तिरुपुर) में विनिर्माण रोजगार गति प्राप्त कर सकते हैं। आयातित उत्पादों के लिए नए माध्यमों और यहां तक की स्थानीकरण पर आधारित बड़े औद्योगिक क्लस्टर्स को स्थापित कर भी नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं (जैसा कि मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए नोएडा और चेन्नई में पहले ही हो चुका है।

श्रम केंद्रित लघु स्तर की सेवाएं

सेवा क्षेत्र में पिछले दशक में उच्च स्तर के रोजगार की ज्यादातर वृद्धि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT पर आधारित सेवा क्षेत्र के जरिए हुई, जो अब पहले से कहीं बेहतर सॉफ्टवेयर स्वचालन और साथ ही साथ अमेरिका में इनसोर्सिंग की तरफ वापस से लौटने के चलते मंदी का सामना कर रही है। ऐसे में, हमें एक बार फिर से खुदरा और थोक व्यापार, संग्रहण और माल भण्डारण, परिवहन और संचार जैसे दूसरे सेवा क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि की संभावनाएं तलाशनी होंगी।

पर्यटन में बहुत से रोजगारों की संभावना है, जो कि एक मिले जुले ढंग का सेक्टर है। ग्रामीण और छोटे कस्बाई इलाकों से लेकर धार्मिक स्थानों के स्तर पर और नए पर्यटन स्थलों का विकास कर नए रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, जैसे- झारखंड में बैजनाथ देवघर, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप, मध्य प्रदेश में मांडू जैसे ऐतिहासिक स्थल और ओडिशा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जैसे सुदूर स्थित वन्यजीव पर्यटन क्षेत्र। व्यवसाय और व्यक्तिगत सेवाओं जैसे क्षेत्र भी सेवा क्षेत्र में रोजगार वृद्धि के बड़े क्षेत्र हैं, जैसे- रियल स्टेट सेल्स एंड मैनेजमेंट, कॉल सेंटर्स, डेटा सेंटर्स और पर्सनल ग्रूमिंग, मनोरंजन और मनोविनोद इत्यादि। इनमें से ज्यादातर सेवाएं निजी सेक्टर में दी जाती हैं और राज्य को केवल 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के बैनर तले सुगम नीतियां बनानी हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना है कि इससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को भी फायदा हो।

अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगारों की सुरक्षा के लिए पथ विक्रेता (जीविका सुरक्षा एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 जैसे कानून को उसकी मूल भावना के साथ लागू करने की जरूरत है। जी. एस. टी. की प्रक्रिया जिसमें ऑनलाइन तरीके से रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी शामिल है, वो लाखों सूक्ष्म उद्यमों के लिए दुर्भर है और इसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। केवल बड़े भुगतानकर्ताओं को ही कम्प्यूटरीकृत तरीके से जी. एस. टी. भरने के लिए कहा जाना चाहिए, जबकि छोटे भुगतानकर्ता वार्षिक तौर पर और संक्षिप्त स्तर पर रजिस्ट्रेशन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं, वहीं सूक्ष्म उद्यमों को जी. एस. टी. भरने की ही जरूरत नहीं होनी चाहिए।

स्वास्थ्य और शिक्षा, लोक प्रशासन और वित्तीय सेवाओं जैसी सामाजिक सेवाएं निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों में बड़े स्तर की रोजगार प्रदाता हो सकती हैं। हमने अलग-अलग सरकारी वेबसाइट्स से डेटा इकट्ठा किया है, जो बताता है कि शिक्षकों से लेकर पुलिस कर्मचारियों तक लगभग 20 लाख सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं।

3.3 क्रियापद्धति और मॉडल

वर्ष 2023 में जी. डी. पी. लगभग 272 खरब रुपये थी। 30 फीसदी की मौजूदा निवेश दर पर इससे 82 खरब रुपये प्रति वर्ष का निवेश पैदा होता है, और जैसे-जैसै अर्थव्यवस्था बढ़ेगी वैसे-वैसे यह निवेश भी हर साल बढ़ेगा। इसके साथ ही, कुल निवेश को बढ़ाने के लिए नीतिगत स्तर पर एक दूसरा परिवर्तनशील भी हो सकता है। घरेलू बचत को बेहतर बनाकर और साथ ही साथ विदेशी निवेश को आकर्षित कर ऐसा किया जा सकता है। घरेलू निवेश सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों से होना चाहिए, वास्तव में निजी क्षेत्र से अधिक।

हमने एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था साल दर साल अपनी जी. डी. पी. का केवल 30 फीसदी हिस्सा निवेश करेगी। यह आंकड़ा 24 से 40 फीसदी के बीच झूलता रहा है। मुख्य नीतिगत फैसला यह है कि आखिर किस तरह से अलग-अलग सेक्टर्स में निवेश किया जाए ताकि लक्षित रोजगारों की संख्या हासिल की जा सके, और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये रोजगार अच्छे भत्ते वाले हैं और उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि पैदा कर रहे हैं। निवेश का ज्यादातर हिस्सा खर्च होगा क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्जीवन पर।
यह अलग-अलग सेक्टर्स में नीति निर्देशित निवेश के पुननिर्यतन के लिए एक मजबूत दलील है, जिसमें अधिक सार्वजनिक निवेश रोजगार पैदा करने वाले चार क्षेत्रों की तरफ मोड़ा जाएगा। मुख्य तौर पर सार्वजनिक निवेश की जरूरत साझा संपत्ति संसाधनों को पुनर्जीवित करने में होगी। लेकिन एक बड़ा नीतिगत हस्तक्षेप नए आर्थिक ढांचे को विकसित करने के लिए जरूरी होगा।

सार्वजनिक निवेश का एक दूसरा बड़ा हिस्सा निम्न स्तर के आधारभूत ढांचे जैसे ग्रामीण और जिला स्तर पर सड़कें, पुल, बाजार अहाते, और लोक सेवा के प्रावधान, जिनमें स्वास्थ्य, साफ-सफाई, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कानून एवं व्यवस्था, और न्याय का प्रशासन शामिल हैं। निजी निवेश के लिए हमारा अनुमान है कि यह मुख्यत: निर्माण, विशेष तौर पर निम्न आय आवासन; अति सूक्ष्म एवं लघु विनिर्माण- हस्तशिल्प, हथकरघा, बिजली से चलने वालीं वस्त्र निर्माण मशीनों; लकड़ी एवं धातु के उत्पाद; सीमेंट, सेरेमिक, शीशे और प्लास्टिक के उत्पाद; इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, हाथ से चलने वाले उपकरणों और मशीनों और लघु स्तर के सेवा क्षेत्र में जाएगा। इन क्षेत्रों में भी निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया जा सकता है।

अलग-अलग क्षेत्रों में नीति निर्देशित निवेश के रोजगार पर असर का मूल्यांकन करने के लिए हमने एक साधारण आर्थिक मॉडल प्रयोग किया है, जिसके बारे में हमने नीचे बताया है। इसकी शुरुआत हमने मुख्य परिवर्तनशील का विवरण देकर की है। मॉडल दिखाता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश स्तर का रूपांतरण करने से अलग-अलग स्तर का रोजगार पैदा होता है।

प्रत्येक सेक्टर में निवेश के समान स्तर पर प्रति इकाई निवेश पर अलग-अलग स्तर के रोजगार पैदा होते हैं, ऐसे में हमने रोजगार के स्तर को बढ़ाने के लिए निवेश वितरण का अंतर-क्षेत्रगत अनुकूलन किया है। यही मुख्य नीतिगत परिवर्तनशील है।

3.4 मॉडल के परिणाम

उच्चतर रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में निवेश का अनुकूलन

जॉब यंत्र हमें यह दिखाता है कि अलग-अलग क्षेत्रगत वितरण का रोजगार और साथ ही साथ वृद्धि पर क्या असर पड़ता है, और इस तरह से यह मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन के लिए जगह बनाता है। सारणी 2 दिखाती है कि प्रत्येक सेक्टर में उनके निर्माण के लिए कितने निवेश की जरूरत है। यह मॉडल आंतरिक तौर पर इस मायने में सटीक है कि वृद्धिशील पूंजी-उत्पादन अनुपात के अनुमानों के साथ, वही निवेश पांच सालों के लिए प्रति वर्ष औसतन 6.02 फीसदी की जी. डी. पी. वृद्धि दर को भी पैदा करता है।

हमारे मॉडल के अनुमानों के मुताबिक, नीति-निर्देशित अंतर-क्षेत्रगत निवेश वितरण के जरिए, 2024 से 2029 के बीच 7 करोड़ 6 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार पैदा किया जा सकता है। इसमें से, एक करोड़ 14 लाख लोगों के लिए क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करने के क्षेत्र, दो करोड़ 14 लाख लोगों के लिए आवासन और लघु स्तर के इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण क्षेत्र, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (MSE) विनिर्माण में एक करोड़ 14 लाख और एक करोड़ 28 लाख लोगों के लिए लघु स्तर के व्यापार, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी, वित्तीय और निजी सेवाओं के क्षेत्र में रोजगार पैदा किए जा सकते हैं। यह 7 करोड़ 6 लाख रोजगार का 80 फीसदी हिस्सा है, यानी कुल 5 करोड़ 70 लाख रोजगार, और ऐसा केवल अर्थव्यवस्था में 50 फीसदी निवेश के जरिए संभव है।

सारणी 2: प्रत्येक सेक्टर में निर्मत रोजगार और आवश्यक निवेश

सेक्टर	2024-29 के दौरान कुल निवेश खरब ₹ में	कुल निवेश में सार्वजनिक हिस्सा % के तौर पर	2024 -29 के दौरान सार्वजनिक निवेश खरब ₹ में
कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण	14	10 %	1.4
क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन	14	90 %	12.6
निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर	43	30 %	12.9
विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	29	10 %	2.9
लघु स्तर की सेवाएं	43	60 %	25.8
अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर	143	10 %	14.3
कुल	**285**	**25 %**	**70**

सारणी 3, 2024 से 2029 की समयावधि के बीच प्रत्येक सेक्टर में पैदा हुए रोजगार दिखाती है। इसके साथ ही साथ यह सारणी क्षेत्रगत रोजगार और रोजगार के क्षेत्रगत हिस्से को भी दर्शाती है।

सारणी 3: अलग-अलग सेक्टर्स में कई सालों के दौरान रोजगार में परिवर्तन

	रोजगार लाखों में	कुल रोजगार के % के तौर पर क्षेत्रगत रोजगार	रोजगार लाखों में	कुल रोजगार के % के तौर पर क्षेत्रगत रोजगार
सेक्टर	**2024**		**2029**	
कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण	194.3	42.9	195.8	37.4
प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन	5.4	1.2	16.8	3.2
निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर	40.3	8.9	61.7	11.8
विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	34.4	7.6	45.8	8.8
लघु स्तर की सेवाएं	97.4	21.5	110.2	21.1
अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर	81.1	17.9	93.2	17.8
कुल	**453**	**100**	**524**	**100**

रोजगार के त्रिविमीय फैलाव का अनुकूलन

क्षेत्रों का चुनाव अपने आप में पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार वहां पैदा हों जहां आबादी रहती है, ताकि अनैच्छिक प्रवास को कम से कम किया जा सके। केवल ग्रामीण और शहरी वितरण की जगह, हमने रोजगार के त्रिविम वितरण प्रारूप का प्रयोग किया है।

ग्रामीण- वो गांव जहां की आबादी पांच हजार से कम है, ऐसे करीब 6 लाख गांव हैं, यहां पर प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

जिला मुख्यालय और छोटे कस्बे, इनमें विनिर्माण क्लस्टर्स को भी शामिल किया जाएगा- साल 2024 तक इनकी संख्या 75000 होने का अनुमान है और हम सुझाव देंगे कि शीर्ष 1000 पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

बड़े शहर और महानगर- इनमें महानगर और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहर और कुछ और इलाके शामिल हैं। इनकी संख्या लगभग 120 है।

ग्रामीण इलाकों से बड़े शहरों में प्रवास को रोकने के लिए- मॉडल दो तरह से काम करता है: ग्रामीण इलाकों में रोजगार बढ़ाया जाए और इसे और आकर्षक बनाया जाए। रोजगार की संख्या क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने के क्षेत्र में बढ़ाई जा सकती है, इस बीच कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वानिकी में लंबे समय तक उत्पादकता और आय को बेहतर बनाया जा सकता है।

जैसा कि कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों के रोजगार में किसी उल्लेखनीय वृद्धि का अनुमान नहीं लगाया गया है, कामगारों को उत्पादकता का एक बड़ा हिस्सा बढ़े हुए भत्ते के तौर पर मिलेगा। यह कृषि रोजगारों को और आकर्षक बनाएगा और कामगारों के खेती छोड़ने के ट्रेंड पर रोक लगाएगा। इसके बाद भी, कृषि में कामगारों का हिस्सा घटता रहेगा।

नीचे दी गई सारणी 5 तीनों त्रिवमीय श्रेणियों में सब-सेक्टर के आधार पर रोजगार में सर्वोत्कृष्ट अनुमानित वृद्धि को दर्शाती है। ये आंकड़े उसी जॉब यंत्र से निकले हैं इसलिए ये क्षेत्रगत निवेश चुनावों और इसके परिणामस्वरूप पैदा हुई वृद्धि के साथ लगातार एक जैसे हैं। जैसा कि देखा जा सकता है कि रोजगार में सबसे बड़ी 3 करोड़ 71 लाख की वृद्धि जिला मुख्यालयों और छोटे कस्बों में है।

इसके मुकाबले ग्रामीण इलाकों एक करोड़ 21 लाख और बड़े शहरों एवं महानगरों में 2 करोड़ 14 लाख की रोजगार वृद्धि है। निर्माण, MSE विनिर्माण और लघु स्तर के सेवा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार संभावनाएं पैदा करना तभी संभव है, जब जिला मुख्यालयों और क्लस्टर्स में निवेश शुरू किया जाए, जो कि 100 तथाकथित स्मार्ट सिटीज (इस भाग में मेहरोत्रा भी देखें) के मुकाबले अगले 1000 वृद्धि केंद्र हैं।

सारणी 5: इलाके के आधार पर रोजगार में परिवर्तन

सेक्टर	2024-29 के दौरान इलाके के आधार पर रोजगार में वृद्धि लाखों में			
	ग्रामीण इलाके	जिला मुख्यालय और छोटे कस्बे	बड़े शहर और महानगर	कुल
कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण	1.3	0.1	0.0	1.4
क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन	6.8	3.0	1.5	11.4
निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर	1.6	13.2	6.6	21.4
विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	1.1	6.8	3.4	11.4
लघु स्तर की सेवाएं	0.6	8.1	4.1	12.8
अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर	0.6	5.8	5.8	12.1
कुल	**12.1**	**37.1**	**21.4**	**70.6**

रोजगार वितरण का कौशल के आधार पर अनुकूलन

2024 से लेकर 2029 तक अगले पांच साल के लिए रोजगार में क्षेत्रगत स्तर पर बेहतरी का अनुमान लगाने के बाद हमने प्रत्येक सेक्टर के तहत कौशल संयोजन की मांग पर नजर डाली। इसके लिए हमने अलग-अलग सेक्टर्स के विशेषज्ञों से चर्चा की।

क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने के क्षेत्र को मुख्य तौर पर अकुशल और अर्धकुशल कामगारों की जरूरत होगी, यद्यपि पर्यवेक्षक स्तर पर कुशल कामगारों की जरूरत होगी। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में कुशल और अर्धकुशल कामगारों की मांग बढ़ जाती है और हमने जिन लोक सेवाओं का प्रस्ताव दिया है, उनमें यह मांग अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है।

सारणी 4: अलग-अलग क्षेत्रों में कई सालों के दौरान कौशल के आधार पर रोजगार में परिवर्तन

सेक्टर	2024-29 के दौरान कौशल के आधार पर रोजगार में वृद्धि			
	अकुशल और कम-कुशल	अर्धकुशल और कुशल	उच्च-कुशल और पेशेवर	कुल
कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन, वनीकरण	1.1	0.2	0.1	1.4
क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों का पुनर्जीवन	9.1	1.4	0.9	11.4
निर्माण- आवासन और लघु इन्फ्रास्ट्रक्चर	12.8	6.8	1.7	21.4
विनिर्माण- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	5.7	5.1	0.6	11.4
लघु स्तर की सेवाएं	6.4	5.1	1.3	12.8
अर्थव्यवस्था के बाकी दूसरे सेक्टर	3.6	5.5	3.0	12.1
कुल	**38.9**	**24.1**	**7.6**	**70.6**

3.5 निष्कर्ष

सारांश में, भारत में 2024 से 2028 के बीच 7 करोड़ रोजगार पैदा करने के लिए, हम चार मुख्य रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में उल्लेखनीय निवेश का प्रस्ताव रख रहे हैं:

- क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करना- जैसे जिन जलाशयों में गाद जमा हो चुकी है, मर रहीं जलधाराएं, प्रदूषित नदियां, खराब हो चुकी मिट्टी, क्षीण हो चुकीं चारागाहें और छंट चुके जंगल, ये सब छोटी अवधि में रोजगार की एक बड़ी संख्या पैदा करेंगे। यह पुनर्जीवन फिर कृषि, पशुधन, मत्स्य पालन और वनीकरण क्षेत्रों के पुनुरुत्थान के लिए पूर्वशर्त के तौर पर काम करेगा।

- निर्माण- कम आय वाला आवासन और साथ ही साथ निम्न स्तर का इन्फ्रास्ट्रक्चर (ग्रामीण और जिला सड़कें, पुल, स्कूल और स्वास्थ्य सेवा केंद्र इमारतें, एक्सप्रेसवे, तेज गति से चलने वाली रेलों, मेट्रो रेल, बड़े एयरपोर्ट्स के मुकाबले)।

- सूक्ष्म उद्यमों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प और अधिक क्लस्टर्ड, निर्यात-केंद्रित लघु उद्यमों, और यहां तक की कुछ आयात स्थानीकरण आधारित मध्यम एवं दीर्घ उद्यमों के जरिए विनिर्माण।

- लघु स्तर की सेवाएं- अनौपचारिक क्षेत्र में खुदरा व्यापार, जबकि संगठित खुदरा क्षेत्र में और रोजगार पैदा होंगे, ई-कॉमर्स और थोक व्यापार, माल भण्डारण और परिवहन, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स, लीक से हटकर पर्यटन, व्यावसायिक, वित्तीय और निजी सेवाएं।

सुझाए गए आधार पर अंतर-क्षेत्रगत निवेश के वितरण के लिए, हमने माना है कि क्षीण हो चुके प्राकृतिक संसाधनों को फिर से जीवित करने के क्षेत्र में ज्यादातर सार्वजनिक निवेश खर्च होगा, इसमें थोड़ा हिस्सा निजी निवेश का भी होगा, यह प्रोत्साहन और नए ढांचे पर आधारित होगा ताकि फायदा सुनिश्चित कर निजी निवेश को आकर्षित किया जा सके।

त्रिविमीय वितरण के संबंध में, हम यह सुझाव दे रहे हैं कि 1000 जिला और क्लस्टर आधारित छोटे कस्बों में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए निवेश किया जाए और इन इलाकों को आर्थिक तौर पर आकर्षक बनाया जाए, ये इलाके आर्थिक वृद्धि की चालक शक्ति के तौर पर काम करें और 100 तथाकथित 'स्मार्ट सिटीज' का विकल्प बनें।

जैसा कि देखा जा सकता है कि रोजगारों की एक बहुत बड़ी संख्या अकुशल कामगारों के लिए है लेकिन अर्धकुशल और कुशल श्रेणी के रोजगारों में भी उल्लेखनीय तौर पर वृद्धि का अनुमान है, इससे कामगारों के भत्ते भी बेहतर होंगे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वृद्धि में किया गया निवेश बड़ी संख्या में अच्छे भत्ते और बेहतर काम की परिस्थितियों वाले रोजगार पैदा करें, नीतियों को कामगारों के लिए और हितकारी बनाना होगा और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि संस्थान प्रभावी ढंग से काम करें।

बेहतर भत्तों को बस कानून बनाकर सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है- बेहतर भत्ते बेहतर उत्पादकता और साथ ही साथ कामगारों की मोलभाव करने की शक्ति (मजदूर संगठनों और श्रम कानूनों के जरिए) का योग हैं, ताकि उन्हें उनकी उच्च उत्पादकता का उचित हिस्सा मिले।

यद्दपि, रोजगार चर्चाएं लगभग पूरी तरह से कामगारों की संख्या और बेरोजगारों पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं, अगर हमें लंबी अवधि में बेहतर श्रमिक उत्पादकता चाहिए तो अब समय आ गया है कि हम रोजगार चर्चा में व्यावसायिक सुरक्षा, कामकाजी स्थितियां और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को शामिल करें। हम 7 करोड़ रोजगार निर्माण नहीं तलाश रहे हैं, बल्कि सात करोड़ बेहतर आजीविकाओं की तरफ देख रहे हैं।

3.6 संदर्भ सूचि

1. CMIE (2018), अनएंप्लॉयमेंट इन इंडिया: ए स्टेस्टिकल प्रोफाइल, मई-अगस्त 2018, सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी, मुंबई

2. महाजन, विजय (2021) "भारत में आजीविका की स्थिति एवं परिणीति" https://www.accessdev.org/wp-content/uploads/2022/06/soil-report-2020.pdf

3. मेहरोत्रा, संतोष (फरवरी 11, 2019), "द शेप ऑफ जॉब क्राइसिस", द हिंदू

4. मेहरोत्रा, संतोष और सरमिष्ठा सिन्हा (2017), "एक्सप्लेनिंग फॉलिंग फीमेल एंप्लॉयमेंट ड्यूरिंग ए हाई ग्रोथ पीरियड", इकॉनमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, LII.39, पीपी. 54–62.

5. मेहरोत्रा, संतोष (2023) श्रमबल एवं रोज़गार वृद्धि पर बहस (न्यू इंडियन एक्स्प्रेस, 3 जून 2023) https://www.newindianexpress.com/opinions/2023/jun/03/the-jobs-and-labour-debate-under-scrutiny-2581238.html

6. MoSPI (2018) नेशनल अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स 2018 URL: http://mospi.nic.in/node/17651

7. NSSO (2019): पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) (जून 2017- जून 2018) URL:http://www.mospi.gov.in/sites/default/files/publication_reports/Annual%20Report%2C%20PLFS%202017-18_31052019.pdf

8. रेजी, प्रशांत (2019), एंप्लॉयमेंट इन इंडिया: स्ट्रक्टरल प्रॉब्लम्स एन एनालिसिस ऑफ एंप्लॉयमेंट सिचुएशन एंड द वे अहेड. पॉलिसी वॉच, अप्रैल 2019, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परारी स्टडीज, नई दिल्ली URL : http://www.rgics.org/wp-content/uploads/Policy-Watch_April2019.pdf

9.. सिन्हा, जे एन (1967): "डायनमिक्स ऑफ फीमेल पॉर्टिसिपेशन इन इकॉनमिक एक्टिविटी इन ए डेवलपिंग इकॉनमी", प्रोसीडिंग्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉन्फ्रेंस, बेलग्रेड, पीपी 336-37

4) Workshop Report:
Conservation linked entrepreneurship and sustainable development of mountain districts of Uttarakhand

Jeet Singh, RGICS

4.1 Introduction

Traditionally, the subsistence of the Indian Himalayan Region is embedded in the forest conservation such as natural farming, livestock and village industries. However, due to the cumulative effect of a number of factors including degradation of natural capital, climate change, modernized economy and changing aspiration of mountain youth have led to deterioration of these Himalayan economic activities. The challenge today is to revive the culture of conservation linked livelihoods in these mountains and transform them to addresses current market demand and changing aspirations of youth.

While there are very few enterprises in the Indian Himalayan Region, in the last two decades, a number of new conservation linked livelihood initiatives have come up. Many of them are successful and inspiring. The growth of conservation linked entrepreneurship solely depends on promoting and maintaining ecological richness of natural resources on which they are dependent. For example, production of premium organic agricultural products depends on healthy soil, eco-tourism depends on richness of landscape and quality honey production depends on preservation of indigenous honey bees and their habitation. In addition to this these entrepreneurship meet the following targets.

1. Proactive efforts to assess local ecology and inbuilt systems in the business to develop and conserve it.
2. Conservation of the ecosystem is a collective task, so all these enterprises inherently involve local communities as partners in the business.

With objectives to create entrepreneurship mindset of young aspiring entrepreneurs and motivate them to start and develop conservation linked enterprises using appropriate technology, technique and ecology a three days workshop was conducted in Urgam village of Chamoli district from 14 to 16 December 2023.

The Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies (RGICS) as part of its ECO LABS program in Uttarakhand collaborated with local organization- Gramya Sikshan Paryavran Sanstha (GRAMYA) to organize this workshop entitled ‘Role of Conservation Linked entrepreneurship in the Sustainable Development of Mountain Districts of Uttarakhand’. The Uttarakhand State Council for Science and Technology (UCOST) provided financial support to organize this workshop. RGICS provided intellectual and knowledge support to local organization to ideate and organize this workshop.

This workshop was attended by 49 micro entrepreneurs from Joshimath, Dasholi and Karnaprayag block of Chamoli district. Of these 30 participants were women and 19 were men. 16 women entrepreneurs who participated in this workshop have started their enterprises through National Rural Livelihood Mission. All of these women entrepreneurs are associated with SHGs and cooperative federations.

15 participants were part of a federation for organic producers promoted by a local NGO- HIMAD SAMITI. Other participants took part in the workshop through our invitation. Micro enterprises started by these participants include poultry, organic production, millet processing, dairy, tourism (home stay and transport) and Mushroom cultivation.

4.2 Entrepreneurship mindset

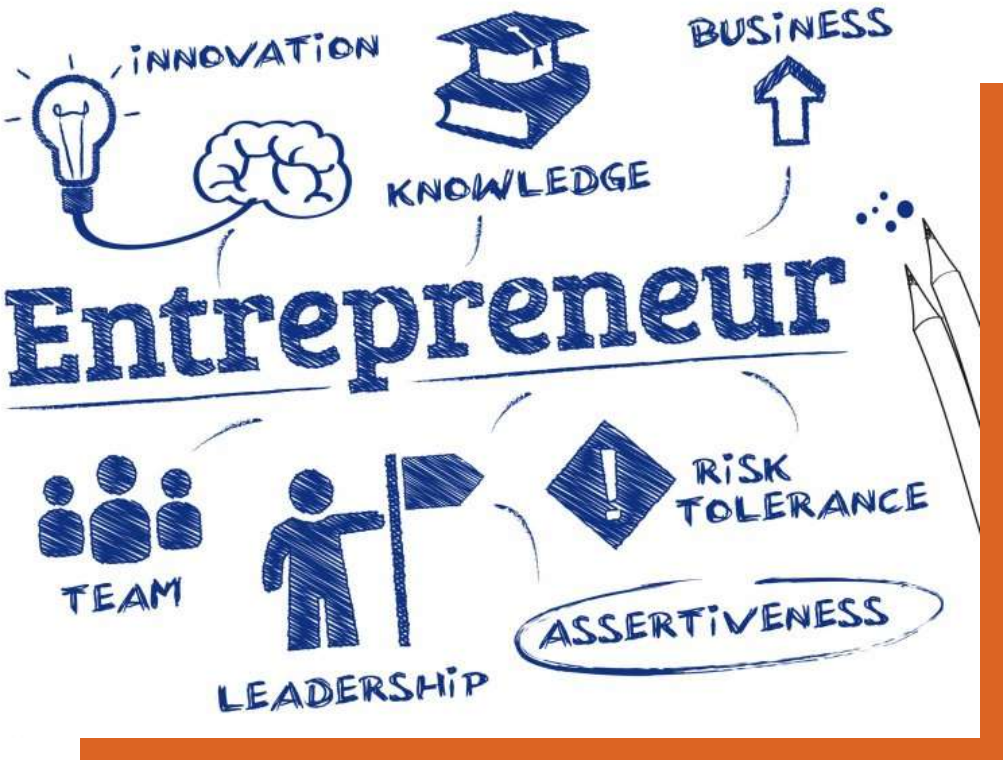

Source: https://www.inc91.com/uploads/images/202110/image_750x_61641f2d3a4c5.jpg

Entrepreneurship mindset is an ability and skill to create new business. These abilities and skills are crucial for any successful business. Development of an enterprising mindset for a micro entrepreneur for whom this workshop was organized is important as most of them have not studied business administration and management.

These skills and abilities include critical thinking, problem solving, adaptability, self reliance, future orientation, collaboration, team building, creativity and innovator. This list is not exhaustive as many other abilities and skills develop entrepreneurship personality that leads to creation of new enterprises. In the context of ecologically friendly enterprises the environmental awareness and conservation sensibility also needed to develop this mindset.

This session was conducted by Dr. Birendra Aswal, Assistant Professor, Sri Dev Suman Uttarakhand University (Gopeshwar Campus). In his address, Dr. Aswal observed that most of the micro entrepreneurs invited in the workshop are new entrepreneurs but without any formal business studies. He stressed that if we are aware of the basic entrepreneurship mindset, we can grow in our business creation. In his deliberation, he focused on following skills and abilities of an entrepreneur:

1) Risk Taking: Dr. Aswal argued that an entrepreneur must be a risk taker. Without risk no business can be created. However, he cautioned that as most micro entrepreneurs have limited resources, people must take calculated risk. Take risks which you can comfortably afford.

2) Quality of the Product: The quality of the product is the key of any business. You can compete in the market only if your product is competitive in the market in terms of quality.

3) Value Addition: Value addition improves and expands our business. Value addition not only makes the product expensive but also increases the shelf life of the product and decreases the volume of the product. He stressed that we must think of value addition in order to expand our business.

4) Branding: Branding is yet another way to popularize and reach out to our customers. He said that located in Himalaya we can brand our product in a much better way compared to many other regions.

5) Awareness of Government Schemes: There are many government schemes that promote development of enterprises in the state. As an entrepreneur we must be aware about various schemes and policies of the state and central government promoting entrepreneurship. In many cases the government is giving subsidies and other incentives. As micro entrepreneurs, people must take advantage of such schemes to reduce their risk and access larger market facilities provided by the government.

6) Marketing: mere production of quality products is not enough. As an entrepreneur, people must also focus on better marketing. For marketing, finishing of product, presentation and packaging play a vital role.

7) Funds and Loan: Funding for new entrepreneurs is always a challenge. For micro entrepreneurs it is suggested to not go for market loans. Rather, it is advisable that they should go for subsidised loans or interest free loans.

In this session Mr. Suresh Dimari, Director, Chamoli Zila Sahkari Bank, Mr. Rakesh Gairola, Founder, Subodh Prem Vidya Mandir and Mr. Jeet Singh, Head of Research, RGICS, participated as discussant. Mr. Dimari observed that the cooperatives were introduced in this country to bring cooperation in business. Giving examples of Amul and other successful cooperatives, he argued that working with fellow entrepreneurs is the key to the cooperative movement. He also informed that the Chamoli Zila Sahkari Bank is giving interest free loan for entrepreneur development in the district. Mr. Rakesh Gairola observed that an entrepreneur is not dependent on any other person or institution, rather he or she provides employment to others.

4.3 Significance of conservation linked entrepreneurship in Uttarakhand

Conservation linked entrepreneurship identifies and addresses three problems namely ecological, social and economic. Conservation linked entrepreneurship distinct themselves from business as usual. Their growth solely depends on promoting and maintaining ecological richness of natural resources on which they are dependent. For example, production of premium organic agricultural products depends on healthy soil, eco-tourism depends on richness of landscape and quality honey production depends on preservation of indigenous honey bees and their habitation.

This session of the workshop was conducted by Mr. Jeet Singh, Head of Research, RGICS. Participants were given an overview of conservation linked enterprises and their social, ecological and economic significance. With the help of brainstorming with participants, he also explained how most of the entrepreneurs operated by participants related to dairy, poultry, mushrooms, honey and millet production are actually conservation linked enterprises. He further explained 11 different steps to start and operate such enterprises. These steps are as follows:

1. **Awareness of social and ecological problems-** the awareness of social and related ecological problems is the first step to start an enterprise which is linked to ecological conservation.
2. **Inspiration-** the second step is ignition of inspiration to solve the identified social and ecological problem using business as a tool.
3. **Ideation of Problem and Solution-** this step requires conversion of inspiration into development of a business idea to solve the identified social and ecological problems.
4. **Experimentation, Trial and Error:** the fourth step is to experiment with ideas and learn from trial, success and failures.
5. **Market Determination-** market determination for product and service is crucial. We must keep it in mind that our product and services are heavily loaded with good social and environmental causes. We must explore and determine our market, which values these causes.
6. **Core Team-** A team is necessary to build and expand a business. A good and compatible team members can lead to faster and successful growth of a business.
7. **Initial Funding-** funding is required to start the business and operate it. Entrepreneurs may choose grants, low cost loans or interest free loans to meet initial demand of fundings.
8. **Minimum Viable Product-** an entrepreneur must narrow down to a market fit product, which can be easily marketed in the determined market.
9. **Enterprise Entity-** there are a number of organization structures available for business. The founder of an enterprise in consultation with team members has to decide the most appropriate type of organizational structure needed for their business. These structures may include the company, cooperative, NGO or Self Help Group.
10. **Funding-** greater funding is required for the expansion of business, which can be explored once the business has completed all previous nine steps.
11. **Business Planning and Sustainable Operation-** a business owner must be visionary and future oriented. Entrepreneurs must plan the business as per the available resources, funding, raw material to ensure sustainability of the operation.

In this session Mr. Birendra Rawat (Poultry Entrepreneur) and Mr. Laxman Singh Negi, Secretary, JANDESH participated as discussants. Both of these resource persons elaborated the idea of conservation linked entrepreneurship and their social, ecological and economic contribution.

4.4 Enterprise Ecosystem for Green Development in Uttarakhand

On the second day of the workshop two sessions were organized under the broad theme of 'Enterprise Ecosystem for Green Development in Uttarakhand'. Under this theme two sessions, one on 'National Rural Livelihood Mission' (NRLM) and another on 'Rural Enterprise Acceleration Project' (REAP) were organized.

4.5 National Rural Livelihood Mission

The Uttarakhand State Rural Livelihood Mission is implementing the National Rural Livelihood Mission in the state to improve economic conditions of poor and rural people by creating economic opportunities and promoting entrepreneurship in the state.

Mr. Mohan Negi, Block Mission Manager of NRLM conducted this session by explaining the purpose of the program and how it is structured to support livelihoods of rural poor people in the state. He informed the participants that the NRLM is well designed to provide support for rural people to start economic activities. These supports provided by the program include formation of SHGs, federating different SHGs at village and cluster level, enhancing access to credit, providing grants, offering technical and market services and building capacities and skills of the poor for gainful and sustainable livelihood.

The State Mission is committed to increase the income of women under the project 'Lakhpati Didi'. The goal is to increase the income of women to one lakh rupees per annum by promoting multiple livelihood options. Under this scheme, the mission is working towards reaching out to about 2.5 lakh households in the state.

Source: https://www.wur.nl/upload/52b6218c-0df2-4f47-aa75-aba08c693097_Social_farming_shutterstock_363795839.jpg

The program has been working and supporting multiple livelihood options both farm based and non-farm activities. To start micro and mini enterprises, the government is providing grants through SHG federations and low cost loans through banks.

Training and capacity development is another important aspect of the NRLM, under which a variety of skill development training is being offered to women SHG members registered under the program. The mission has collaborated with professional training institutions to impart free of cost training on a number of skills, so that trainees can start their micro enterprises.

Mr. Negi informed that the Mission is opening for innovative and new technology based training and entrepreneurship. For example, recently they organized 15 days residential training for women to weave baskets made out of ecologically invasive 'Lantana' grass. He further argued that if, lantana basket improves as a business, it solves many social, ecological and economic problems.

Livelihood promotion activities require long term hand holding support especially in rural areas with limited resources and knowledge inflow. The mission is therefore the process of cadre building at local level to sustain the implementation of NRLM.

The mission is now providing training to local women called 'Sakhi' on different issues such as dairy, poultry, millet processing, food processing, fruit processing etc. These Sakhis will act as local resources for villagers to start and operate micro and mini enterprises.

Towards the end of his deliberation, he also touched upon the village and cluster level organizational set-up of SHGs and their federations. He also explained available financial (loan and grants), technical and market resources available for SHG members. He concluded that the elaborated structure of SHGs creates an effective ecosystem for enterprise development at the grassroots level.

4.6 Rural Enterprise Acceleration Project (REAP)

The next session in this theme was on the Rural Enterprise Acceleration Project (REAP) of the Uttarakhand Gramya Vikas Samiti (Government of Uttarakhand).

The REAP project commissioned by the state government and funded by the IFAD aims to double the income of rural households.

This project is being implemented in collaboration with Uttarakhand State Rural Livelihood Mission. The approach of the project is to build resilience of rural households by diversifying their sources of income. The project is implemented in 95 blocks of 13 districts in Uttarakhand.

Assistant Manager of REAP in Chamoli district Mr. Rajbar Bisht in this session explained the objective, operation and opportunities provided by the REAP for rural entrepreneurs of Uttarakhand. REAP has been working with individuals, SHGs and SHG federation.

It provides financial, technical, market and skill support to individual entrepreneurs. Under this project a grant of Rs. 35,000 is being provided to poor women to start a livelihood activity. Moreover, it provides technical and HR support to SHG federation or FPOs to scale up their businesses.

REAP has three major components through which it aims to accelerate rural enterprises in Uttarakhand. The first component is ‘Inclusive Cluster Development’.

Under this component efforts are being made to work at cluster levels by diversifying livelihoods and enterprise development. This component also supports organizational development of SHGs and Federations

The second component of the project is ‘Ecosystem for Enterprise Development’. In this component efforts are being made to provide infrastructure related facilities and market linkages. Attempts are also made to provide financial assistance for the acceleration of rural enterprises.

The third component of the project is Project Management and Knowledge Management. Under this scheme services related to project management and knowledge management are offered to rural enterprises for their acceleration.

Poultry entrepreneur Mr. Birendra Singh Rawat and Mr. Umashankar Bisht, Secretary, HIMAD Samiti participated as discussants in these two sessions under the theme of ‘Enterprise Ecosystem for Green Development in Uttarakhand’.

Mr. Rawat argued that enterprises are built on local raw material, climate and natural resources. In mountain districts of Uttarakhand, the abundance of natural wealth provides ample scope for conservation linked livelihoods.

Mr. Umashankar argued that the growth of women entrepreneurs associated with SHG federations can be accelerated if women are given exposure, training and opportunities, and also their need for financing is met by banks through the SHG federations.

4.7 Conservation responsibilities and value added livelihoods

4.7.1 Value Added Processing of Sweet Oranges (Malta)

The idea of green growth attempts to explore and economically harness symbiotic relationships between social and ecological systems. Instead of environmental tradeoff this economic approach believes in co-benefits.

Two sessions under this theme were conducted on the second day and another two sessions were conducted on the third day of the workshop.

The first session under this theme was conducted by Entrepreneur, Innovator and Educationist Mr. Rakesh Gairola. In his deliberation he shared his experience of innovating technologies and enterprises to address local problems.

Source: Image

Mr. Gairola started with his enterprises to address the problem of throwing away market price of sweet orange (malta) in Mandal valley near Gopeshwar town. He explained that the malta was never competitive in the market as easy edible oranges from Nagpur are preferred over it by customers. To address this problem, Mr. Gairola developed technology and machines to process Malta and increase their shelf life in the form of juice and jams.

Further he developed technology to utilize flavido of malta to utilize it for cosmetic products. The leftover of malta after extraction of juice is also used as bio enzymes. Today, as an entrepreneur Mr. Gairola is utilizing every part of Malta and profitably running his business by providing employment to 64 people.

Mr. Gairola has further added that his endeavor to develop technologies to sustainably harness the natural wealth motivated him to find solutions for developing enterprises in the sector of lantana oil extraction and restoration of dumping grounds in Uttarakhand.

In his concluding remarks, he added that for an entrepreneur, one must have scientific temperament. A true entrepreneur has the capacity to find a solution to a problem. And finding a solution is Science. Science and technology is crucial for the growth of any business. It helps enterprises to compete in the market.

4.7.2 Responsible Tourism

The second session of the day under the theme of 'Conservation Responsibilities and Value Added Livelihoods' was conducted by Mr. Laxman Negi, Secretary, JANDESH. In his presentation, Mr. Negi explained the prevalent tourism practices in Uttarakhand and how it is adversely affecting local ecology. He argued that irresponsible behavior of tourism and unregulated inflow is highly damaging and leaves an irreparable impact especially in high altitudes. He further argued that the economic contribution of the tourism sector in Uttarakhand is negligible despite the fact that about 50% of tourists in the Indian Himalayan region visit Uttarakhand.

Talking about solutions, he advocated for premium and high end tourism in Uttarakhand. He argued that this tourism will enhance our economy substantially and also reduce pressure on natural wealth significantly. He further stated that currently tourism is operated without understanding the carrying capacity of the local landscape. Innovation in tourism is required by identifying unique and interesting tracks, landscape and natural beauty to attract premium tourists.

Mr. Negi also argued that homestays are a good way to enhance the rural economy. However, he cautioned that we must not dilute the idea of homestay with commercial hotels. Homestay idea brings cultural aspects in tourism. And premium tourists are more interested in culture along with landscape. We can greatly benefit from blessed natural wealth and deep rooted cultural practices.

Ms. Prabha Rawat, President of Gramya Sikshan Paryavaran Sanstha Ms. Susheela Bhatt, Principal, Subodh Prem Vidya Mandir, Gopeshwar participated as discussant in these two sessions. Ms. Rawat argued that high end tourism needs to be promoted to have tourism in a sustainable manner. Further, the local culture must be harnessed to make tourism more interesting, attractive and profitable. Ms. Bhatt argued that co-benefiting entrepreneurs such as fruit processing, restoration of dumping grounds and natural oil extractions must be promoted in the highly fragile Himalayan region.

Source: Image

4.7.3 Enterprising Traditional Apiculture

The third day of the workshop started with continuation of theme Conservation Responsibilities and Value Added Livelihoods. Under this theme the first session was delivered by Mr. Prakash Panwar, an entrepreneur.

Mr. Panwar shared his experience of learning bee keeping and transforming it into a micro entrepreneur. He stated that his encounter with honey bees was random, when he observed people collecting honey through traditional methods. It instigated him to inquire more about it and find ways to adopt it as a source of income. His quest to learn about honey bees exposed him to learn about various species of honey bees, their culture, colony, honey production and honey harvesting.

Mr. Panwar further added that he realized that boxed beekeeping promoted through various schemes are not successful at micro level, as they can be easily eaten up by wild animals. For boxed beekeeping one needs better protection and guarding of honey bee boxes.

He motivated participants to continue with wall beekeeping, which is traditional practice in Uttarakhand. However, he motivated people to use modern tools and techniques to effectively harvest honey, protect honey bees and process honey as per market demand.

Source: https://www.rpcau.ac.in/wp-content/uploads/2017/11/Training-1.jpg

4.8 Carbon sequestration and trading of credits

The second session under this theme on the third day of the workshop was conducted by Mr. Jeet Singh, Head of Research, RGICS. His presentation was on the concept of carbon credit, Indian policy mechanism to yield benefits of carbon credits and opportunities for Himalayan farmers and entrepreneurs.

He stated that the idea of carbon credit has dual benefits as it improves the local ecology which helps in sequestration of higher amounts of carbon. On the other hand, the additional amount of sequestrated carbon can be sold in national and international markets at a very high price.

Mr. Singh stated that the government of India has recently introduced the Carbon Credit Trading Scheme and also drafted the Green Credit Scheme guidelines.

Mr. Mohan Negi, Block Mission Manager, NRLM and Entrepreneur Mr. Sidhant Arora participated as a discussant in this session. Mohan Negi argued that honey is a premium product if it is harvested and processed well. He further argued that marketing, packaging and branding is required to sell honey of the region in the premium market.

Mr. Arora stated that entrepreneurs change with time. Carbon sequestration is a global demand, but it can provide opportunities for micro entrepreneurs to benefit from it by restoring his or her own agriculture land and forest. More information and systemic support is needed to facilitate entrepreneurs to take up twenty first century businesses.

4.9 Accessibility of technology and techniques to entrepreneurs

Entrepreneurs participating in the workshop were divided in five sub-groups based on their enterprise and enterprising interests namely millet processing, dairy, mushroom cultivation, poultry and organic farming. These groups were further asked to discuss in groups, share their experiences, technology, science and techniques to enrich understanding of each one of them. They were further asked to discuss technological advancement and techniques required for the growth of their enterprises.

The group on millet processing summarized their discussion and informed the larger group that technologies for milling of local millets such as Jhangora, Kauni and Koda are not well developed. It takes a lot of time and energy to mill these millets. The over consumption of milling of these millets increases the input cost leading to low profit.

Source: Image

The group on dairy informed that most people have one or two cows and produce very limited milk. However, most people are unaware about cow rearing, selection of fodder, selection of cow species and feeding techniques. Group highlighted the requirement of better draining to make dairy a high profit business.

Mushroom cultivation was smaller, as very few of them were involved in mushroom cultivation. These participants informed that the local demand for Mushrooms is very high; however, they don't have enough space and resources to cultivate Mushrooms in large quantities.

The poultry group informed the larger group that it can be a very profitable business if we can reduce the input cost by having a local hatchery. Currently, poultry farmers are dependent on hatchery located in Saharanpur and Punjab. The transportation all the way to Chamoli increases the input cost.

The final group on organic farming stated that, despite having a certificate of organic production, they don't have access to a suitable market, where it can be sold at premium prices. This group demanded the need for a market mechanism for locally produced certified organic products.

Source: Image

Source: Image

4.10 Major takeaways and recommendations

Policy and Programs: Resource persons and participants of the workshop highlighted issues related to shortage of infrastructural and institutional mechanism in mountain district of Uttarakhand to develop enterprising mindset and enterprising culture. Moreover, they also stress on effective implementation of schemes and programs of the government to promote entrepreneurship in the region.

Promotion of New and Innovative entrepreneurship: New and innovative enterprising sectors may be promoted in mountain districts such as clean energy, green credit and information technology.

Market Preference: Social and ecological entrepreneurs in mountain districts with limited resources can grow by tapping the high end and premium market, for example, high end tourist and premium organic consumers.

Appropriate Technology: More regionally appropriate technological advancement is required to process and value addition of local resources such as millets, sweet orange, lantana, grains and fruits.

Reduction of dependency on out of state inputs: Reducing dependency for fodder, feed and hatchery increases input cost of enterprises related to dairy, fisheries and poultry. Local hatchery and fodder production units can be developed to boost micro enterprises in the region.

Trainings Requirement: There is huge demand for training especially in the dairy sector. Micro entrepreneurs participating in our workshop feel that in the absence of proper training their dairy business is less profitable.

Incentive of Eco-Friendly Businesses: Special incentives may be provided to conservation-linked entrepreneurs in mountain districts of Uttarakhand as they are solving social and economic problems at the local level and ecological problems at the global level.

5) India’s Foreign Policy since 2014: Continuity and Change

Sneha Mahapatra, RGICS

“For over 30 years, India's foreign policy evolved under a relatively stable constellation of circumstances... It provided a framework of reference which did not change too much from one year to the next. It provided a set of fairly unvarying certainties against which India could test the usefulness or otherwise of any policy option at a given point of time.” [1]

Source: https://d376x96w2eszl1.cloudfront.net/research1696751284.jpg

5.1 Introduction: why was 2014 a watershed?

Though domestic factors have had a significant influence on the trajectory of Indian foreign policy, the continuities of non-alignment had prevailed for the first three decades through changes in leadership and electoral vicissitudes. Since gaining independence, India has seen three distinctive electoral phases, as identified by political scientist Yogendra Yadav.

“Initially, from 1952, the Congress party dominated, while opposition remained fractured. However, in 1967, Congress faced significant state-level defeats, signaling the decline of its supremacy. The second phase, lasting from 1967 to 1989, witnessed Congress holding power in Delhi mostly but encountering challenges from regional, often caste-oriented parties in the states. Then, from 1989, a coalition-based political landscape emerged, marking the onset of the third electoral system. This system, spanning over 25 years, introduced key shifts: heightened national-level competition, tighter margins in parliamentary contests, increased influence of regional parties, stagnant national voter turnout, and a more decentralized electoral scenario. The 2014 election results, however, compel a reassessment of these principles.” [2]

In 2014, Mr Narendra Modi and the Bharatiya Janata Party (BJP) emerged victorious. The BJP managed to win 282 of 543 seats in India's lower house of parliament (the Lok Sabha), the first time a single party won a majority in three decades. The Congress tally, meanwhile, sunk to just 44 seats—down from 206 in 2009. In 2019, the BJP increased its seats in the Lok Sabha to 303, enabling it to bring major legislative changes. The BJP government led by Mr Modi has signalled a move away from even the rhetoric of non-alignment, with significant implications for the future of Indian foreign policy.[3]

Mr Modi's overarching vision has been to present an India to the world that is "uninhibited", secure, developed and prosperous. In this context, Mr Modi's foreign policy encompasses elements of: pride of place to relations with neighbors, leveraging the capacities of all countries, particularly major players, for promoting India's development, hedging against a rising China, safeguarding India's national interests, and harnessing the Indian diaspora for furthering the country's interests.

Shifting its gaze inwards, India's foreign policy under Mr. Modi sees its immediate surroundings as fertile ground for mutual growth. Recognizing that its own progress inextricably intertwines with a harmonious neighborhood, India has placed its South Asian neighbors at the forefront of its diplomatic efforts. This commitment, personified by the presence of SAARC leaders at Prime Minister Modi's inauguration, reflects a new chapter in India's regional engagement."[4]

By exploring how India has operationalized the policy, this article maintains that to some extent continuity will persist: India will likely continue its rhetoric of strategic autonomy while moving closer to the West and its allies in practice. Yet in order to effectively balance China's growing influence, India will need to be more assertive in building these alliances, as the success of its pursuit of strategic autonomy rests on the strength of its strategic partnerships.

5.1.1 From Non-Alignment to Multi-Alignment: Redefining India's Foreign Policy

Independent India was born in very difficult circumstances. Freedom came with the partition of the country. It was in this situation that independent India started on its journey to achieve several objectives while grappling with a myriad of challenges, both internal and external. Internally, the country pursued economic development through a series of Five-Year Plans, with a focus on industrialization, infrastructure, and agrarian reforms. The Green Revolution in the 1960s and 1970s marked a significant stride toward achieving food security.

Externally, India faced geopolitical challenges, including the Sino-Indian War in 1962, resulting in territorial losses to China. Additionally, the complex relationship with Pakistan led to multiple conflicts, notably the wars in 1947-48, 1965, and 1971.

This post-independence era witnessed the nation's multifaceted journey toward economic growth, food security, and diplomatic balancing in a dynamic global landscape including adopting non alignment as a pragmatic foreign policy.

---

[1] *Pran Chopra (1991) Foreign Policy in a Changing World, Economic and Political Weekly, Vol. 26, No. 14 (Apr. 6, 1991)*

[2] *https://carnegieendowment.org/2014/06/10/new-era-in-indian-politics-pub-55883*

[3] *India's 'non-alignment' conundrum: a twentieth-century policy in a changing world*

[4] *https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine*

With the onset of the Cold War, Indian political figures were compelled to respond to the United States of America's Policy of Containment (or the Truman Doctrine) under which the US would provide political, military, and economic aid to democratic countries under the threat of communist influences in order to prevent the expansion of communism.[5]

Prime Minister Jawaharlal Nehru responded to the Cold War rivalry by forging India's foreign policy on the principles of Panchsheel, prioritizing mutual respect and peaceful coexistence. He actively engaged with the United Nations, advocating for decolonization and disarmament. On the world stage, Nehru played a pivotal role in establishing the Non-Aligned Movement, offering a path for nations to navigate the Cold War without aligning with any major power bloc.

However, the Sino-Indian War in 1962 highlighted the need for strategic alliances and military modernization, leading to closer ties with the Soviet Union. Through these policies and engagements, Nehru laid the foundation for India's emergence as a major player in international affairs, committed to global peace and cooperation.

In the Cold War's shadow, India faced security threats from neighbors and rising communist powers. To protect its borders, Indian leaders made practical alliances with regional countries and led the Non-Aligned Movement. This cautious balancing act secured India's territory and carved a unique role for it on the world stage.[6]

From the 1960s to the 1990s, India's foreign policy navigated a complex web of wars, alliances, and internal shifts. The 1965 war with Pakistan over Kashmir highlighted the enduring tensions, while the Tashkent Declaration sought to mend ties. The USSR became a key ally, providing military and economic support, even as the US offered food aid through PL 480.

Source: Image

[5] https://history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine

[6] https://carnegieendowment.org/2019/04/04/bjp-and-indian-grand-strategy-pub-78686

While India faced the shadow of China's nuclear arsenal, pursuing its own weapons was neither feasible nor desirable. Instead, India chose avenues for diplomacy and restraint. Nehru's 1954 "standstill agreement" echoed the Soviet proposal for a regional "no first use" pact. It was a step towards broader Asian nuclear disarmament.

The Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT), born from decades of Cold War limitations, stood as a powerful tool – though not yet ratified – that India could champion, aligning with the US suggestion to address China's nuclear concerns within regional agreements.

By actively promoting CTBT ratification and advocating for transparency measures, India built trust and reduced tensions, paving the way for lasting peace efforts as envisioned by engaging in multilateral dialogues and prioritizing non-proliferation further strengthen this approach. This further demonstrated India's commitment to a nuclear-free future without escalating the regional arms race. Rooted in diplomacy and historical precedents, this path offered a sustainable and secure future for India in the face of China's nuclear shadow.[7]

Indira Gandhi's era saw significant developments. The 1971 war and creation of Bangladesh cemented India's regional power status. The Indo-Soviet treaty solidified their close relationship, while India's 1974 nuclear test sparked international concern. Gandhi also played a role in establishing SAARC, promoting regional cooperation, though she did not live to attend the first summit at Dhaka in 1985; that role was performed by her son, Rajiv.

Rajiv Gandhi's era maintained the Soviet partnership while getting involved in the Sri Lankan civil war. He kickstarted economic liberalization, a precursor to the "LPG reforms" in the 1990s.

Source: Image

[7] https://www.proquest.com/openview/7128c64b2504afcebc7897e6fef5f0dc/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Narasimha Rao's tenure saw a shift toward economic liberalization and closer ties with the West, focusing on trade and foreign investment. His "Look East" policy, launched in 1991, aimed to strengthen political, economic, and security cooperation with Southeast Asian countries. Rao's "Look East" Policy was taken forward by PM I K Gujral (April 1997 - March 1998). Although Gujral was PM for less than a year, he is the only Prime Minister with a foreign policy approach identified with his name — the Gujral Doctrine, which guided relations with South Asian neighbours. The Gujral Doctrine consisted of five basic principles, as outlined in his Chatham House speech in London in September 1996:

"First, with the neighbours like Nepal, Bangladesh, Bhutan, Maldives and Sri Lanka, India does not ask for reciprocity but gives all that it can in good faith and trust. Secondly, no South Asian country will allow its territory to be used against the interest of another country of the region. Thirdly, none will interfere in the internal affairs of another. Fourthly, all South Asian countries must respect each other's territorial integrity and sovereignty. And finally, they will settle all their disputes through peaceful bilateral negotiations." [8]

Later, he explained in his autobiography: "The logic behind the Gujral Doctrine was that since we had to face two hostile neighbours, we had to be at 'total peace' with all other neighbours in order to contain Pakistan's and China's influence in the region."

It is good to remember, before becoming PM, Gujral had served as Foreign Minister for two terms. So, in June 1997, BIST-EC (Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand - Economic Cooperation) was formed which six months later was expanded to BIMST-EC to include Myanmar. With Nepal and Bhutan joining as full members in 2004, the organization was rechristened BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative on Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). Beginning with 14 priority sectors of cooperation, the number was reduced to a manageable seven during the Colombo summit of March 2022.

Prime Minister Modi's priority of strengthening relationships with neighboring nations, recognizing the pivotal role of peace in South Asia for India's developmental agenda, is actually a continuation of India's foreign policy in the neighbourhood. His proposal to introduce paradiplomacy suggests granting states and cities the autonomy to foster unique connections with other countries, signaling a shift in India's global engagement strategy.

However, most states lack the necessary structural framework to effectively manage engagements, exhibiting either unwillingness or incapability to engage in meaningful dialogues with consular staff from foreign nations keen on fostering investments. Therefore, it is crucial for the individual states in India to establish a comprehensive knowledge base tailored to the pertinent states or provinces of the countries they aim to establish para-diplomatic relations with.[9]

The "Act East" policy prioritizes Southeast Asia, forging strong economic and security ties with nations like Vietnam and Japan. Closer to home, the "Neighbourhood First" approach rekindles relationships with South Asian neighbors, aiming for regional stability and mutual benefit. In the Indian Ocean, Mr Modi counters China's growing influence through maritime partnerships with Rim countries, while Project Mausam fosters cultural and trade linkages across the region.

---

[8] https://indianexpress.com/article/explained/explained-politics/what-is-gujral-doctrine-significance-9049011/

[9] *India Quarterly, vol. 73, no. 4, 2017, pp. 375–94. JSTOR, https://www.jstor.org/stable/48505555. Accessed 8 Jan. 2024*

Even the distant Pacific Islands witness India's growing presence through the Forum for India-Pacific Islands Cooperation. Ultimately, Mr Modi's foreign policy seeks to position India as a regional and global leader, securing its strategic interests, fostering economic prosperity, and strengthening cultural ties across the globe.

5.1.2 Trade and Technology

India's foreign policy is experiencing a paradigm shift, with technology evolving from a mere economic driver to a potent diplomatic instrument. Its strategic partnerships with tech giants like the US and EU, exemplified by initiatives like the U.S.-India iCET focusing on AI and 5G/6G collaboration, and the EU-India Trade and Technology Council (TTC) tackling trade-tech challenges, paint a vivid picture of this transformation.

However, India's ambitions transcend mere self-gain. Its active role in the Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) and the International Research Center on Artificial Intelligence (IRCAI) underscores its commitment to ethical and inclusive AI development. Furthermore, India champions digital public infrastructure (DPI) as a key accelerator for Sustainable Development Goals (SDGs).

Source: Image

At present, trade relations are at a point of transition as technology and foreign policy increasingly intersect. Pervasive technological forces have brought radical social change, forced governments to innovate, and prompted new approaches for how governments and citizens interact. Catchphrases are emerging each day to describe this trend, like- 'tech diplomacy or techplomacy', 'cyber diplomacy', and 'digital diplomacy.'[10]

[10] https://southasianvoices.org/the-tech-moment-in-indias-foreign-policy/

The G20 Digital Economic Ministerial Meeting under India's presidency, which witnessed the ground-breaking consensus on DPI as an SDG enabler, stands as a testament to this leadership. This outward focus is also evident in India's domestic endeavours. The establishment of specialized tech divisions within the Ministry of External Affairs, like the New Emerging and Strategic Technologies Division (NEST Division), demonstrates a proactive approach to navigating the complexities of emerging technologies.

This internal expertise fuels India's active participation in shaping global tech governance, as seen in its contributions to the development of standards and regulations for areas like AI and cyber security. However, India's tech diplomacy faces challenges. Data privacy concerns linger in the wake of initiatives like Aadhaar, while concerns about digital divides within India itself highlight the need for balanced growth.[11]

In a speech to the nation on 12 May 2020, Prime Minister Modi announced his new concept of economic self-reliance (Atmanirbhar Bharat). Its historic roots lie in the Swadeshi movement, which advocated the preferential use of domestically produced goods and whose ideas are also reflected in the writings of the RSS. Albeit under different political conditions, India had already pursued a course of import substitution starting in the 1950s. At that time, the country was oriented towards socialist economic models and relied on a large state sector. Ultimately, by the time it ended in 1991, this policy only spurred an average growth of about 3.5 per cent.

it is important to acknowledge here that despite actively pursuing trade agreements for export growth, India hasn't enjoyed unequivocal success. Currently, India has 14 Regional Trade Agreements (RTAs) in force with a dozen more under negotiation; findings from NITI Aayog's report on India's performance in FTAs highlighted that total exports to FTA countries have not outperformed total exports to rest of the world.

More specifically, FTAs with ASEAN, South Korea and Japan in the past have all instigated the trade deficit to increase significantly. For the fiscal year 2019, India registered a trade deficit with 11 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) member countries, signifying that trade pacts are not only about gaining access to markets in other countries but also giving market access to the trade partners.

Source: Image

[11] https://southasianvoices.org/the-tech-moment-in-indias-foreign-policy/

Studies reveal that overall exports haven't significantly outperformed non-agreement nations, often trailing behind surging imports, widening the trade deficit. Agreements with ASEAN, South Korea, and Japan stand out for historically exacerbating this imbalance, raising concerns about the RCEP's potential impact. Past difficulties in negotiating balanced deals further fueled apprehensions about RCEP, leading Indian policymakers to tread cautiously, wary of worsening the deficit.[12]

Mr Modi's current concept, on the other hand, aims at privatising often unprofitable state-owned enterprises, commercialising agriculture and building up national business champions, for example, in the technology sector.

Prominent critics, such as Mr Modi's former economic advisor Arvind Subramanian, object to this path, noting that no developing country after the Second World War has been able to achieve growth of more than 6 percent through domestic demand alone.[13] The policy of self-reliance is in line with the "Make in India" programme that was introduced in 2014, which aims to increase exports and reduce imports.[14]

Source: Image

5.2 Elements of Change and Continuity

5.2.1 India US relations – ups and downs

India's relationship with the United States has been marked by periods of both tension and cooperation. During the Cold War, India's non-alignment policy created distance, while the US saw it as too close to the Soviet Union. However, the 1970s nuclear test led to US sanctions, creating further strain.

India and the United States shared certain key interests and perceived them alike. While some American observers, through misunderstanding, miscast India as an enemy ally, the general US view acknowledged India's non-alignment. Moreover, India, unique among developing nations, embraced democracy, further solidifying its alignment with Western values.

---

12 https://www.orfonline.org/expert-speak/india-reluctance-joining-rcep-boon-bane-long-run#~:text=For%20the%20fiscal%20year%202019,access%20to%20the%20trade%20partners

13 https://www.swp-berlin.org/10.18449/2021C30/

14 https://dam.gcsp.ch/files/2y10NglVtodrmscPeADoEPMuu59qGSGn3rBtYW6cOndix7QEZaYZjIO

Source: Image

The relationship began to thaw in the early 2000s, culminating in the landmark civil nuclear agreement, paving the way for closer ties and India's inclusion in the international non-proliferation regime.[15] Since the 1990s, economic ties have flourished, making the US one of India's major trading partners and a significant source of investment.[16]

The aftermath of the September 11 attacks further strengthened cooperation on counterterrorism, with joint military exercises and intelligence sharing agreements solidifying the partnership.[17] In recent years, the two nations have actively pursued a "strategic partnership," focusing on defense and security cooperation, with the Indo-Pacific region being a key area of collaboration.

From India's perspective, the US relationship held strong appeal due to their extensive and fruitful people-to-people ties, exceeding those with any other industrialized nation. Trade relations also proved beneficial, occasionally surpassing those with the Soviet Union. Notably, India relied heavily on the US for high-tech imports, receiving critical food aid during times of hardship.

Further bolstering the relationship were US-facilitated development loans and investments, crucial for securing foreign exchange despite their relative insignificance compared to India's total development expenditure. Finally, the US served as a valuable counterweight to countervailing forces in the region, adding weight to the multifaceted benefits of a strong India-US relationship.[18]

In 2005, a transformative "global partnership" bloomed between India and the US. Leaders Singh and Bush pledged to strengthen ties across diverse sectors. The economic engine revved up with a CEO forum and a focus on infrastructure, trade, and knowledge sharing in agriculture.

Energy security, cleaner technologies, and sustainable development received a boost. A global initiative tackled democracy-building and HIV/AIDS, while a new defense framework and disaster relief measures bolstered security.

---

15 *https://carnegieendowment.org/2022/09/20/russia-and-india-new-chapter-pub-87958*

16 *https://www.economist.com/asia/2019/06/29/india-presents-america-with-a-choice-between-geopolitics-and-trade*

17 *https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2021/01/FP_20210111_us_india_white.pdf*

18 *ibid*

The US embraced India's burgeoning civilian nuclear program, paving the way for future cooperation with safeguards and controls in place. This landmark agreement ushered in a new era of comprehensive US-India partnership, promising a future of shared prosperity and progress.[19]

Prime Minister Modi's US visit in June 2023 yielded a number of agreements across trade, security, and foreign policy. Trade received a major boost with US investments in India's chip manufacturing and deeper maritime cooperation through the Indo Pacific Oceans Initiative. On the security front, defence deals for drones and jet engines solidified the US as a key partner, while the launch of 'INDUS-X' fostered closer defence industry collaboration.

Space exploration cooperation reached new heights with India joining the Artemis Accords and agreeing to a joint human spaceflight mission. Even visa procedures eased with a pilot program for domestic H1B renewal. Despite looming concerns about democratic backsliding in India, Mr Modi's visit marked a significant stride in the progression of the US-India relationship. [20]

Source: Image

While several significant achievements in the Indo-US relationship in 2023, there were two incidents in the last quarter that revealed a lack of complete trust in this partnership.

The Biden administration filed a chargesheet in a New York court naming an Indian official in a plot to kill a US national and a separatist Sikh leader on American soil.

The very fact that the U.S. went ahead with the chargesheet on an alleged plot and at the same time has not taken any action against those responsible for the attack on the Indian consulate in San Francisco and openly issuing threats to top Indian diplomats in the US appears to be a clear reflection that a lot is required to be done when it comes to the “trust” and “confidence” between the two largest democracies of the world.

---

[19] *https://www.cfr.org/timeline/us-india-relations*

[20] *https://www.thehindu.com/news/international/us-india-set-to-announce-deals-across-multiple-domains-during-modis-state-visit/article66996997.ece*

The year saw remarkable collaborations, such as the launch of the Critical and Emerging Technology (iCET) initiative and efforts to boost bilateral trade and investment. President Biden's support for crucial deals and eased regulations highlighted a commitment to strengthening ties.

Symbolic events like Mr Modi's rare State Visit and Biden's participation at the G-20 Summit reinforced this bond, demonstrating joint success amid global challenges. Despite these strides, incidents toward the year's end indicated that full trust in this partnership is yet to be achieved.

Source: https://d18x2uyjeekruj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2023/06/icet.jpg

First, was open American support to the allegations made by Canadian Prime Minister Justin Trudeau about a "possible" link between India's government and the killing of a pro-Khalistan separatist in Vancouver.

In less than 100 days, the Department of Justice filed a damaging indictment in a federal court in New York saying that it had unearthed a plot to kill a US national on American soil. Though the separatist Sikh leader was not named, media reports identified him as Gurpatwant Singh Pannun, the leader of the Sikhs for Justice, an organisation banned in India.

India has denied the Canadian allegations and has repeatedly said that Ottawa has not shared evidence on the case. On the US indictment, India has instituted a high-level commission to probe the allegations.

New Delhi is also not happy with the inability of the US to take action against those responsible for the attack on the Indian consulate in San Francisco and openly letting separatist Sikhs organise and propagate anti-India and Khalistani movements in the country. As such, what could have been easily a historic year in the India-US relationship, at best can be described as three steps forward and one step backward.[21]

[21] *https://www.thehindu.com/news/national/india-us-relationship-in-2023-three-steps-forward-one-step-back/article67671436.ece*

5.2.2 India-China relations – tensions persist

India's relationship with China boasts of ancient cultural and economic ties, facilitated by the Silk Road. However, the 19th century saw British exploitation of opium trade between India and China, leaving a lasting mark on their relations. Both nations fought alongside each other during World War II, but the Cold War era saw India recognize the communist People's Republic of China, while maintaining a non-aligned stance. China's close ties with the Soviet Union during this period created further complexities. The 1960s witnessed border conflicts, including the 1962 war, which remain a source of tension.

Although being India's largest trading partner between 2008 and 2021, economic nationalism and ongoing border disputes continue to pose challenges. Despite 18 one-on-one meetings between Prime Minister Modi and President Xi Jinping, China's support for Pakistan and the border disputes further complicate the relationship. Conversely, India's increasing naval presence in the South China Sea and its hosting of Tibetan exiles raise concerns for China. The South Asian region has become a battleground for influence between the two Asian giants, with their rivalry shaping the region's future.[22]

Source: https://knnindia.co.in/uploads/newsfiles/INDIA-China-17-6-2020.jpg

Prime Minister Modi's emphasis on self-reliance represents a stark shift from historical policies, aiming to privatize unprofitable state-owned entities, boost agriculture, and foster national business champions, notably in technology.[23]

India's withdrawal from global trade partnerships, heightened tariff impositions, and increased restrictions on Chinese companies during border conflicts exemplify a protective stance aimed at safeguarding its economic interests. However, these actions underscore significant gaps in understanding global dynamics and emphasize the necessity for a more balanced approach in navigating international relations.

---

[22] *http://in.china-embassy.gov.cn/eng/xwfw/zgxw/201507/P020210622243188059948.pdf*

[23] *http://20.244.136.131/expert-speak/to-convert-atmanirbhar-bharat-into-reality-modi-needs-to-wage-a-war-69171*

While Mr Modi denounced growing global protectionism at the World Economic Forum in 2018, his government began raising tariffs against itself. In autumn 2019, New Delhi withdrew from the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) at the last minute on the grounds that its participation in the free trade project would further widen its chronic trade deficit with China.

Indeed, during its border conflict with China in summer 2020, India's government tightened its restrictions against Chinese companies.[24]

The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) was spearheaded by China as a comprehensive free trade agreement negotiated between the 10 ASEAN Member States and ASEAN's free trade agreement (FTA) partners viz. Australia, China, India, Japan, Korea and New Zealand.

India's withdrew at the last moment in November 2019 from the negotiations of the RCEP – arguably the world's largest trade bloc - because it had massive trade deficits with at least eleven of the fifteen RCEP countries, which had almost doubled after Mr Modi came to power.

It was stated that India wants voluntary economic initiatives like the Indo-Pacific Economic Framework, as opposed to restrictive trade deals like the RCEP, as that resonates with India's self-reliance aspirations.

Yet the trade imbalance with China and the ASEAN countries continues to grow. While bilateral trade deficit remains significant in 2023, India imposed new export controls targeting China, only to be toned down quickly due to tech dependency. This shows that India cannot define strategic ambitions far in excess of its technological and economic clout.

5.3 Departure from Earlier Policy Stances – Three Examples

Departing from the mantle of Nehruvian non-alignment, Mr Modi has spearheaded the forging of strategic partnerships and actively engaging with key regions across the globe.

However, foreign policy experts have argued that India's once-dominant position in Asia is crumbling under the weight of Mr Modi's foreign policy failures.

Island nations like Maldives feel empowered to snub their larger neighbour, while Nepal and Sri Lanka openly embrace China. This stark reversal from India's preeminent position, where its voice was sought on regional matters, stands as a testament to a foreign policy lacking clear objectives beyond promoting Mr Modi's own image.

The absence of a coherent strategy has left India's influence eroding rapidly, raising questions about its ability to navigate the complex geopolitical landscape of the region.[25]

---

[24] https://dam.gcsp.ch/files/2y10NglVtodrmscPeADoEPMuu59qGSGn3rBtYW6cOndix7QEZaYZjlO

[25] https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/truth-lies-and-politics/a-critical-review-of-foreign-policy-of-india-since-1947-part-ii/

5.3.1 India's changing role in global south dynamics amidst China's Ascendancy

India's diminishing participation in summits like the Non-Aligned Movement and G-77, coupled with the reduced engagement in South-South cooperation over the past decade, underscores a departure from its prior active role in Global South activism. This shift, combined with economic challenges and a stance that often falls short of matching China's assertiveness in global forums, contributes to India's declining significance within the Global South.

While historically India and China have employed distinct strategies when engaging with the Global South, India had opted for established platforms like the G-20, Non-Aligned Movement, UN climate change conferences, G-77, and the UN General Assembly to advocate for the Global South's positions. For instance, during the COVID-19 pandemic, India, alongside South Africa, approached the WTO to suspend intellectual property rights on vaccines, aiming to enhance access for low - and middle - income nations. In contrast, China creates alternative, China-led forums such as the Belt and Road Forum, Global Development Initiative, and others.

Chinese rhetoric often carries an implicit anti-Western and anti-American tone, rejecting hegemony and the US-led international order, diverging from India's more moderate stance. However, India faces challenges, primarily in China's rhetoric and economic influence attracting more support from the Global South than India's softer critique of the international order.

China's assertiveness, coupled with its economic offerings, outweigh India's limited resources for similar economic outreach. China's official stance, criticizing global institutions and advocating for a more equitable globalization while emphasizing sovereignty (even amidst territorial disputes), resonates with many in the Global South disillusioned by perceived Western double standards. In contrast, India's approach often falls short in matching China's bold positions, lacking the impact of pointed rhetoric during emotionally charged global events.

India also grapples with its reduced engagement with the Global South over the past decade. A heightened focus on relations with the U.S. and the West led to a decline in South-South cooperation, marking a departure from India's previous active role in Global South activism. This shift is evident in India's diminishing participation in summits like the Non-Aligned Movement and G-77. India's aspiration transcends its current Global South identity, aiming for inclusion among powerful states managing global governance. However, China's intensified drive for influence and leadership in the Global South has prompted India to reassess its rhetoric, diplomacy, and policies.[26]

Source: Image

[26] https://www.foreignaffairs.com/china/how-thwart-chinas-bid-lead-global-south

5.3.2 The I2U2 Grouping: A change in India’s strategic stance in the Middle East

From the shores of the Arabian Sea to the plains of North Gujarat, a novel quartet is drawing curious glances. The I2U2 grouping, comprising India, Israel, the United Arab Emirates (UAE), and the United States, presents a unique platform for cooperation in fields ranging from agriculture to renewable energy. But beyond the immediate projects lies a deeper significance for India's foreign policy and its global aspirations.

First, I2U2 offers a tangible manifestation of India's burgeoning economic ties with the UAE. The initial $2 billion investment and tech assistance for Indian agriculture, targeted at states like Gujarat and Madhya Pradesh, stand as a model for future capital flows. Coupled with Israeli and American expertise, this unlocks new possibilities for development and innovation.

Moreover, I2U2 acts as a catalyst for the ongoing normalization of relations between Israel and the UAE, a process India has historically supported. With closer ties between Jerusalem and Abu Dhabi, India's own strategic partnership with both nations finds further reinforcement. Notably, Prime Minister Modi has shed the hesitance of past generations, openly embracing Israel's crucial role as a supplier of military technology. While the balancing act in West Asia, particularly with regards to Iran, remains a delicate dance, I2U2 provides a valuable diplomatic tool to navigate the region's complex waters.

Source: https://vajiram-prod.s3.ap-south-1.amazonaws.com/I2_U2_245_71c1d0ffd2.jpg

Perhaps the most significant aspect of I2U2 lies in its unique framework for engagement with the United States. Unlike formal alliances or junior partnerships, I2U2 presents a stage for cooperation based on mutual respect and India's "strategically autonomous" stance.

The I2U2 is not merely a collection of projects, as it embodies a strategic convergence that aligns with India's foreign policy priorities: fostering economic growth, deepening regional partnerships, and carving out its own space on the global stage. While challenges remain, I2U2 offers a promising avenue for India to solidify its position in the Middle East.

5.3.2 India's Rice Export Ban: Its Impact on Global South Relations and Food Security"

As of July 2023, India’s decision to ban the export of specific rice has garnered much criticism as it significantly impacts nations in Africa, Latin America, Asia, and the Caribbean, India's export restrictions exacerbate existing challenges. The vulnerability of these nations to food inflation and supply disruptions intensifies due to reduced access to Indian rice varieties, potentially heightening food insecurity and escalating prices for millions reliant on these imports.

This restriction on rice exports raises doubts about India's commitment to global food security and its prioritization of domestic needs over international obligations. The interconnectedness of the world's food systems is highlighted as the ban's ripple effects prompt shifts in trade alliances and dependency patterns, potentially leading to a reassessment of India's role as a reliable rice exporter in the Global South.[27]

Source: https://assets.eenadu.net/article_img/US1a.jpg

[27] https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/view-india-cant-lead-the-global-south-and-not-feed-it/articleshow/102153288.cms

5.4 Shifts in style and substance

5.4.1 Staking a claim to leadership of the Global South

Source: Image

Speaking at Hudson Institute, a think tank in Washington DC on the topic of ‘India’s Role in a New Pacific Order,’ Jaishankar said India aims to reorder the world not with a 'pull down the pillars' approach, but with a reformist mindset where India would add a non-Western layer to the existing world architecture.[28]

In discussing “re-globalization”, he highlighted the evolving nature of the current model over the past 25 years, pointing out that India's presence and activities have notably increased in the east, extending into the Pacific and beyond. He noted that India's heightened contribution to shaping a Pacific order reflects an ongoing process of rebalancing. "This rebalancing is driven centrally by the United States' altered capabilities, positioning, and attitudes," he clarified. "It is also a complex process influenced crucially by the rise of China and its far-reaching implications.”

Jaishankar delved deeper into the simmering discontent within several countries regarding the global economic structure. He highlighted a pervasive sentiment of resentment brewing over the last couple of decades, exacerbated by events such as the COVID-19 pandemic and the Ukraine conflict, leading to surges in energy and food prices.

Countries increasingly felt exploited as mere resources fuelling the economy of other nations, although he was careful not to lay the blame solely on the West. He was emphatic that his stance wasn't in support of the West, shedding light on the complexities of today's globalization, emphasizing how manufacturing concentration, often bolstered by subsidies, detrimentally affects diverse economies. India, however, stands out in manufacturing, agriculture, scientific achievements like the Chandrayaan-3 mission, and successful vaccination drives.

[28] https://thewire.in/diplomacy/india-is-non-western-not-anti-western-jaishankar-calls-for-re-globalisation

These accomplishments have fostered a strong sense of identification among the Global South, including the African Union, as India embodies the potential for growth and progress. Moreover, Jaishankar discussed India's impactful stewardship during its presidency of the G-20 Summit. He highlighted achievements such as steering influential nations toward a trajectory of growth and development and directing attention toward initiatives focused on the Global South. Jaishankar voiced apprehensions about Canada's political sheltering of the Khalistan group, highlighting the potential threats posed by such allowances on the global stage.[29]

A recent instance highlighting this disparity emerged during the election for a Vice President's position on UNESCO's Executive Board held on November 24. Surprisingly, Pakistan secured a significant victory with 38 votes to India's 18, despite its internal turmoil with a caretaker government and a struggling economy, not to mention its continued association with extremist ideologies and terrorism. India's loss by such a wide margin was unexpected given Pakistan's current state.

".. the Ministry of External Affairs which is responsible for all aspects of India's external engagements, should have read the tea leaves of this election better. This is .. because it opens up questions… on India's efforts' efficacy with countries of the Global South."[30]

Moreover, this setback isn't an isolated incident. India faced challenges in key diplomatic matters, such as the unsuccessful extradition of Devy, a Danish national involved in an arms case, and apparent lapses in effectively handling the case of Italian marines, raising concerns about the tracking of the legal proceedings, both in Rome and domestically.[31] There was a recent incident where eight former Indian Navy personnel working in Qatar ere charged ith spying and sentenced to death. It took adroit diplomacy and a meeting by the Prime Minister with the Emir of Qatar to get this death sentence commuted.[32]

India's expanded presence and engagements towards the east, along with its emphasis on "neighbourhood first" policy has been marred by domestic policies and a perceived "muscularity" that alienates neighbours. The Citizenship Amendment Act (CAA) angered Pakistan, Afghanistan, and Bangladesh, while the abrogation of Article 370 in Kashmir strained relations with Pakistan and border roads construction strained relations with Nepal. Similarly, the Akhand Bharat terminology and domestic policies have met with pushback from Maldives and Sri Lanka, indicating a disconnect between the government's regional aspirations and its execution.

Source: https://csss-isla.com/wp-content/uploads/2019/12/CAB-Images1.jpg

[29] https://www.thehindu.com/news/national/need-to-get-over-syndrome-that-west-is-the-bad-guy-says-s-jaishankar/article67320584.ece

[30] https://www.ksgindia.com/study-material/today-s-editorial/todays-editorial-23-december-2023.html

[31] https://indianexpress.com/article/opinion/columns/why-despite-deft-diplomacy-india-did-not-get-a-seat-at-the-unesco-table-9079558/%20?

[32] https://indianexpress.com/article/explained/qatar-commutes-death-sentence-indian-navy-veteran-9086293/

5.4.2 Foreign policy recalibration and shift in strategic focus

India's foreign policy in the 21st century navigates a delicate dance between continuity and change, evident in both style and substance. While the core principles of strategic independence and moral leadership remain constant, the way India engages with the world is undergoing a dynamic transformation.

On the one hand, India is shedding its "rule-taker" image, actively shaping the global agenda through platforms like the G20 Summit and COP26. The "Integrated Framework" sheds light on the intricate balancing act behind India's negotiating positions, ensuring national interests are protected while maximizing international leverage. Case studies like the TRIPS Agreement reveal both victories and challenges in navigating complex trade negotiations.

Beyond trade, India's voice is resonating on critical issues like climate change. From pioneering the "Panchamrit" action plan to advocating for "Common but Differentiated Responsibilities," India is moving from highlighting "lifestyle emissions" to leading the charge for a sustainable future. This assertive yet principled approach, exemplified by its stance on the Ukraine-Russia conflict, showcases India's strategic agility and commitment to moral leadership.

In essence, India's foreign policy metamorphosis transcends mere style. It's a substantive shift from cautious defence to proactive shaping, from rule-follower to rule-shaper. This "sui generis" approach holds immense potential for India to not only secure its own interests but also contribute meaningfully to a more equitable and sustainable world order.

The future beckons, and India, with its evolving style and unwavering substance, is poised to claim its rightful place as a leading force on the global stage. India, once a regional hegemon and a champion of non-alignment, finds its foreign policy in flux. Under the Modi government, the country has joined numerous new formations, yet struggles to revive the once-vibrant South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC).

Source: Image

BIMSTEC and BBIN, while promising, fall short of encompassing the entire region. Even the Non-Aligned Movement (NAM), a cornerstone of India's Cold War identity, has seen its engagement wane, with the Modi government's outreach efforts targeting similar countries through alternative channels.[33]

This strategic shift from non-alignment to a nebulous "multi-alignment" leaves India's position in an increasingly polarized world unclear. The government walks a precarious tightrope, navigating the pitfalls of a "please-all" approach that risks pleasing none in the long run. This ambiguity extends to its foreign policy principles, oscillating between pragmatism, realpolitik, and transactionalism without a clear, guiding framework.

China's rise poses a significant challenge, not just bilaterally but across the subcontinent. Every Indian neighbour, except Bhutan, is now part of the Belt and Road Initiative (BRI), attracting unprecedented levels of Chinese investment and trade. Even Bhutan, long considered a close Indian ally, has engaged with Beijing in unprecedented ways to resolve their border dispute. This stands in stark contrast to India's own stalled progress with China, with key objectives like NSG membership and UNSC reform remaining elusive.[34]

Mr Modi’s personalized summit-level diplomacy, once touted as a key strength, has also faced limitations. The failure to anticipate and prevent the 2020 LAC incursions, despite numerous high-level engagements, raises questions about its effectiveness in managing complex geopolitical situations.

While the government's efforts to repatriate Indians stranded abroad are commendable, the case of Kulbhushan Jadhav in Pakistan highlights the limitations of diplomacy without cooperation. International judgments hold little sway without it, as evidenced by the lack of progress in Jadhav's case and similar situations involving Indian nationals in Qatar, Pakistan, and elsewhere.

Persona driven foreign policy

In September 2014, Mr Modi visited the US and addressed the Indian diaspora in New York's Madison Square Garden. He also held talks with Former US President Barack Obama and his "diplomatic showmanship" made headlines in India as well as in the US.

In the following years, Mr Modi developed a close working relationship with Obama. After Donald Trump became America's president, India-US ties continued to flourish, with New Delhi and Washington sealing several trade and defence deals and undertaking joint military exercises.

Over the past few years of his prime ministership, Mr Modi's assertive persona has raised concerns on its long-term effectiveness and potential pitfalls warrant scrutiny.

Furthermore, Mr Modi has drawn criticism for potentially exacerbating internal divisions. Critics argue that his focus on Hindu symbols and practices overlooks India's diverse religious and cultural landscape.

---

[33] https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1895858

[34] https://www.thehindu.com/opinion/lead/indian-diplomacy-non-alignment-to-multi-alignment/article13982580.ece

His unconventional initiatives, like the SARC invite or the Gujarat meeting with Xi Jinping, garner media attention, but their concrete strategic outcomes remain questionable.

Source: Image

For example, Mr Modi's diplomacy being described as “charming” the European Union, as he visited Berlin and Paris in 2015 and held talks with German Chancellor Angela Merkel and Former French President Francois Hollande, has raised questions on “effectiveness of such relations in bringing about positive growth in security, trade, technology, climate, migration, health (to name a few), or simply his way to “overtly rely on personal charisma highlighting concerns about the institutional robustness of Indian diplomacy and his projection of Indian identity.”[35]

Closer to home turf, while Mr Modi’s visit to Nepal was mildly successful, his meeting with Prime Minister Sushil Koirala didn't produce the expected agreements—the Power Trading Agreement and the Project Development Agreement were notably missing outcomes. Though a minor setback, it marked a disappointment. Similarly, the visit to Japan resulted in a substantial investment commitment of $35 billion.

Despite the close rapport between Mr. Modi and Prime Minister Shinzo Abe, often characterized as a "bromance," the anticipated signing of the nuclear agreement between the two nations did not materialize.

Despite spending considerable time together in Kyoto and official meetings in Tokyo, the divergence between Japan's expectations and India's assurances on nuclear testing remained unbridged.

Despite hopes pinned on this visit, the much-anticipated nuclear deal remained elusive. Additionally, other expected agreements like upgrading the strategic dialogue format, securing a deal for US-2 amphibian aircraft, and advancing the commercial agreement for exporting rare earth minerals faced obstacles in the final stages of negotiations.

---

[35] https://www.jstor.org/stable/pdf/45341935.pdf

Critics, exemplified by a scathing article in the Japan Times titled "Showmanship trumps substance during Modi visit" by analyst Jeff Kingston, termed the visit as inconclusive showmanship. However, Indian commentators were more forgiving, acknowledging that many outcomes might unfold over subsequent months and years.

Some solace was found in Australian Prime Minister Tony Abbott's visit, which resulted in a nuclear deal for Uranium imports. The subsequent challenge arose during Mr. Xi's visit. Despite the initial warmth displayed during his visit and the symbolic image of both leaders seated together on a swing in Ahmedabad, Mr. Modi's aspiration for a shift in India-China discourse didn't materialize.

Incidents at the border overshadowed the discourse, and efforts to achieve a stand down of troops failed despite extensive discussions along the Sabarmati Riverfront and in Delhi's official Hyderabad House. One of the drawbacks of this summit-focused diplomacy lies in Mr. Modi's extensive international engagements, stretching himself thin. Additionally, a centralized foreign policy approach often catches the Ministry of External Affairs off-guard, necessitating rapid responses to implement decisions. This pace, combined with a shortage of officers in the MEA, results in reduced preparation and limited follow-up capabilities.[36]

5.5 Conclusion

Mr Modi's leadership persona has taken precedence over principled thought-policy dictating foreign policy objectives. Today he adeptly maintains an image of tirelessly striving to modernize India and elevate its global standing, this begs the question of whether India ever be taken "seriously" as Mr Modi's rhetoric projects it to be "*atmanirbhar*" and highlights India as a *vishwaguru*.

The erosion of India's influence in South Asia, India's severe trade deficit with 11 out of the 15 RCEP countries, and the unresolved border dispute with China, all raise concerns about the country's ability to navigate the complex geopolitical landscape of the 21st century.

Moving forward, India must prioritize a coherent foreign policy strategy that balances its own interests with those of its neighbours, adoption of prudent policies, the pursuit of realistically achievable objectives and a demonstration of continuity of policy, irrespective of changes in the nature of the Administration and the broader international community. In the presence of such structured, deliberate, stringent and self-preserving policies, only then can it reclaim its position as a leader of the global south.[37]

As Abhijnan Rej a former Senior Fellow of the Observer Foundation, New Delhi, and Rahul Sagar, a faculty member of the New York University wrote:

"[In the absence of the cultivation of strength, Mr] Modi's vigorous and pragmatic outreach to other countries around the world and his emphasis on civilizational values as a driver of Indian foreign policy ring hollow, privileging optics over substance." [38]

---

[36] https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/limits-of-summitstyle-diplomacy/article6450200.ece

[37] https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/limits-of-summitstyle-diplomacy/article6450200.ece

[38] https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/limits-of-summitstyle-diplomacy/article6450200.ece

RAJIV GANDHI
INSTITUTE FOR CONTEMPORARY STUDIES

Rajiv Gandhi Institute for Contemporary Studies

Jawahar Bhawan,
Dr Rajendra Prasad Road,
New Delhi 110 001
India

Please visit us at:

www.rgics.org

https://www.facebook.com/rgics/

https://www.youtube.com/user/RGICSIndia